मनेन्द्रगढ़
07 अगस्त 2026 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

दैनिक मीडिया ऑडिटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

खड़गे बोले- क्या मुझे रिजिजू से सीखना पड़ेगा

सदन में बोलना मेरा अधिकार; रिजिजू ने कहा- नए सांसदों को भी मौका दें; शाह संसद पहुंचे

नई दिल्ली,एजेंसी। संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। खड़गे ने कहा- क्या अब मुझे किरेन रिजिजू से सीखना पड़ेगा। वे चेयरमैन के चेंबर में जाकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहां आकर बोलता हूं। अगर मैं नियम नहीं पढ़ूंगा तो क्या उनकी दी हुई चीजें पढ़ूं?

खड़गे ने कहा- क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, यह तय करना मेरा अधिकार है। सत्ता पक्ष हमारे सांसदों का अपमान कर रहा है। मैं सिर्फ अमित शाह के संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा हूं। इस सदन में जेटली जी ने खुद कहा था कि रुकावट लोकतंत्र का हिस्सा है।

इस पर रिजिजू ने कहा- कांग्रेस अध्यक्ष विपक्ष के नए सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक ही मुद्दे पर बार-बार बोलकर समय बर्बाद कर रहे हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के नए सांसद है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं सदन में उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं।

खड़गे की अध्यक्षता में संसद में INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को संसद भवन में INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल सहित सपा और विपक्षी दलों के अन्य नेता शामिल हुए।

आरबीआई गवर्नर बोले: कम मूल्य वाले नोटों से शुरुआत होगी, ये 30 साल तक चलेंगे

नई दिल्ली,एजेंसी। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल-मई के बीच लॉन्च होंगे। यह जानकारी RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, यानी MPC की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा- दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में रहे हैं।

भारत में कागजी नोट, विशेषकर 10, 20 और 50 के छोटे नोट, बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं।गवर्नर ने कहा- पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या नमी से ये खराब नहीं होंगे और बार-बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी कम होगा।

: ब्रीफ बॉक्स :

ट्रम्प बोले- अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद

नए हथियार भी बन रहे, सीक्रेट लीक करने वालों को लंबी जेल होगी

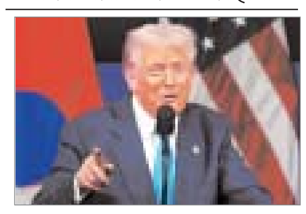

वॉशिंगटन डीसी /तेहरान /तेल अवीव,एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जरूरत के मुताबिक बड़ी मात्रा में हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उनकी सप्लाई भी लगातार की जा रही है।

ट्रम्प के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा कंपनियां देश के इतिहास में सबसे ज्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका की रक्षा उत्पादन क्षमता और मजबूत होगी।

ट्रम्प ने गोपनीय रक्षा जानकारी लीक करने वालों पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ लंबी जेल की सजा की मांग की जाएगी।

केजरीवाल का दावा: उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित

मेटा से जवाब मांगा; कहा- कंपनी सरकार के सामने घुटने न टेके

नई दिल्ली,एजेंसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मेटा से कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आया।

केजरीवाल ने कहा कि उनके पास कई लोगों के मैसेज आए कि उनका अकाउंट भी प्रतिबंधित किया गया। उन्होंने उन लोगों से भी संपर्क करने की अपील की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया- सरकार मेटा पर दवाब डाल रही है कि जो भी व्यक्ति एथेनॉल या पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है, उसके अकाउंट को प्रतिबंधित किया जाए। मेटा इस तरह की बदमाशी न करे और मोदी जी के सामने घुटने न टेके।

सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत

झांसी, प्रयागराज,एजेंसी। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान (21) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह गुरुवार सुबह प्रयागराज से झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। क्रेटा कार में अबान के साथ उसके 4 दोस्त थे। झांसी से 70 किमी पहले सुबह 10.30 बजे पूंछ थाना इलाके में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। अबान समेत सभी 5 लोग अंदर फंस गए। चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने जैसे-तैसे दरवाज तोड़कर सभी को बाहर निकाला। आगे की सीट पर बैठे अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर मौत हो गई। जबकि बाकी 3 घायलों उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम को जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे की दो वजह सामने आ रही हैं। अबान के घायल दोस्त ने बताया कि हाईवे पर ईंट थी, इससे कार अनियंत्रित हो गई। जबकि पुलिस का कहना है कि कार की स्पीड तेज थी। अचानक हाईवे पर आए जानवर को बचाने में कार डिवाइडर से टकराई है।

कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करेगी 'क्या बोलती पब्लिक' कैंपेन

अभिजीत दीपके गांव-शहरों में युवाओं से बात करेंगे बेरोजगारी और महंगी शिक्षा होगी मुद्दा

नई दिल्ली,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके सितंबर से देशभर में 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान शुरू करेंगे। दीपके ने गुरुवार को महाराष्ट्र के संभाजीनगर में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम गांव-शहर जाकर युवाओं से बात करेंगे। साथ ही, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे।

दीपके बोले- बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया जाएगा। हम शिक्षा सुधारों पर काम करेंगे। शिक्षा को मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया है, लेकिन हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।नीट पेपर लीक को लेकर दीपके और उनकी पार्टी ने जंतर-मंतर पर 20 जून से 25 जुलाई तक, लगातार 36 दिनों तक धरना दिया था। 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने धरना समाप्त करने की घोषणा की थी।

दीपके ने कहा- CJP चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी

अभिजीत दीपके ने कहा- CJP कोई चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, बल्कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों और शासन में जवाबदेही तय करने के लिए एक मजबूत पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी।

मकान ढहा परिवार के 6 लोगों की सोते वक्त मौत

● मां-बाप, बेटा-बहू, 2 बच्चे ● कई फीट मलबे में दबे...चीख तक नहीं पाए

प्रतापगढ़,एजेंसी। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के बीच 100 साल पुराना मकान ढह गया। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में माता-पिता, छोटा बेटा, बहू और उसके दो मासूम बच्चे शामिल हैं। 7 लोगों के परिवार में अब सिर्फ बड़ा बेटा जिंदा बचा है।

बुधवार रात गर्मी और उमस के कारण परिवार के सभी 7 सदस्य AC वाले कमरे में सो रहे थे। रात करीब 2 बजे, जब सभी गहरी नींद में थे, तभी अचानक कमरे की छत भरभराकर गिर गई। किसी को संभलने या मदद के लिए चीखने तक का मौका नहीं मिला। छत गिरते ही पूरा परिवार कई फीट ऊंचे मलबे में दब गया। बड़ा बेटा अमन कमरे के किनारे सो रहा था। वह किसी तरह मलबे से बाहर निकल आया और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची।

करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मलबे में दबने और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी करार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा; 2013 में साथी पत्रकार ने आरोप लगाया था

पणजी,एजेंसी।बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के रेप केस में दोषी करार दिया। कोर्ट आज ही सजा सुनाएगी।

इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था।

मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। मामला सार्वजनिक होने के बाद गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज की और जांच शुरू की। जांच में CCTV फुटेज, ई-मेल और गवाहों के बयान समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए।

तहलका में शिकायत, गोवा पुलिस ने FIR दर्ज की... महिला पत्रकार ने सबसे पहले तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ई-मेल भेजकर शिकायत की। इसमें उन्होंने लिखित माफी, पूरे स्टाफ के सामने घटना स्वीकार करने और आंतरिक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति (ICC) गठित करने की मांग की थी।

ऋषिकेश में गंगा वॉर्निंग लेवल पार, घाटों पर जाना रोका

● बद्रीनाथ हाईवे बंद, केदारनाथ में गाड़ियां फंसी ● लुधियाना में सड़क पर 20 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ

नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश आफत ला रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी वॉर्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। लोगों को घाटों पर न जाने की चेतावनी दी गई है। चमोली में हेलंग के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। वहीं, देहरादून, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा के पास पहाड़ से मलबा और पानी केदारनाथ हाईवे पर आ गया। इससे कई गाड़ियां कीचड़ और चट्टानों के मलबे में दब गईं। इधर, यूपी के फर्रुखाबाद के 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में गंगा का पानी घुस गया है। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के कारण 100 साल पुराना मकान ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई।

उधर, असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस मानसून सीजन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। धानसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 1.6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, रास्ता बंद; हेलंग के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर...

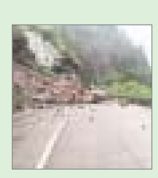

उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के चलते हेलंग के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से सड़क बंद हो गई ये रास्ता सीधे बद्रीनाथ जाता है। हेलंग के पास 200 यात्री रोके गए हैं। प्रशासन ने लोगों से यात्रा न करने की अपील की है। सड़क को जल्द बहाल करने के लिए BRO, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PWD की टीमें लगातार काम कर रही हैं।

अमरनाथ यात्रा फिर शुरू, 1,801 तीर्थ-यात्री जम्मू से बालटाल रवाना

जम्मू,एजेंसी। जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 व 35ए को हटाए जाने की सातवीं बरसी पर बुधवार को सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए रोकी गईवार्षिक अमरनाथ यात्रा गुरुवार को फिर शुरू हो गई। जम्मू के भगवती नगर स्थित संयुक्त पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार, तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तड़के 2:45 बजे भगवती नगर यात्री निवास से बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों के अनुसार, पहलगाम मार्ग के लिए आज भी यात्रियों का कोई भी जत्था नहीं भेजा गया। बालटाल रवाना हुए कुल 1,801 तीर्थयात्रियों में 1,347 पुरुष, 351 महिला, 89 साधु और 14 साध्वियां शामिल हैं। इन सबको 74 गाड़ियों से भेजा गया है। इस गाड़ियों में 40 बसें, 12 मीडियम मोटर व्हीकल, 19 लाइट मोटर व्हीकल और तीन दोपहिया वाहन शामिल हैं। जत्थे के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान चल रहे हैं। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्रमुख तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह यात्रा हर वर्ष जम्मू-कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित भगवान शिव की गुफा (बाबा बर्फानी) के दर्शन के लिए आयोजित की जाती है। यहां हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग (हिमलिंग) निर्मित होता है। अनंतनाग जिले में अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।

जेप्टो, बुक माय शो और इंडिगो समेत 9 एप्स पर लगा 20 लाख रुपये का जुर्माना

डार्क पैटर्न इस्तेमाल करने का आरोप

नई दिल्ली,एजेंसी। आप ऑनलाइन किराने का सामान इसलिए मंगाते हैं क्योंकि आप इतने थक गए होते हैं कि बाजार नहीं जा सकते। आप परिवार के लिए फिल्म के टिकट खरीदते हैं या फिर आप किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए साइन अप करते हैं तो स्क्रीन पर जो कीमत दिखती है, वह ठीक-ठाक लगती है लेकिन पेमेंट करने से ठीक पहले बिल बदल जाता है।

एक हैंडलिंग फीस जुड़ जाती है। एक मेंबरशिप भी जुड़ जाती है। एक छोटा सा डोनेशन पहले से ही टिक किया हुआ होता है। अचानक कोई एक्स्ट्रा सर्विस या सब्सक्रिप्शन भी दिखाई देने लगता है। शुरू में ये रकम छोटी लग सकती है लेकिन दर्जनों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये धीरे-धीरे काफी बढ़ सकती है। सरकार अब ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है।

डार्क पैटर्न इस्तेमाल करने पर 9 एप्स पर लगा जुर्माना: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने नौ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना लगाया है। ये ऐसे वेबसाइट और एप डिजाइन होते हैं जो यूजर्स को ऐसे फैसले लेने के लिए बहका सकते हैं जो वे शायद लेना नहीं चाहते थे। सरकार ने राज्यसभा को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है।

और इस लिस्ट में कुछ बहुत जाने-पहचाने नाम शामिल हैं। जैसे जेप्टो, बुक माय शो, इंडिगो और फिजिक्स वाला।

मेंबरशिप का अपने-आप जुड़ जाना बास्केट स्नीकिंग माना गया। Zepto पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और तब से उसने रेगुलेटर द्वारा बताई गई इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया है। एक ग्राहक के लिए निराशा की वजह साफ है। आपको लगता है कि आप एक रकम चुका रहे हैं। आप पेमेंट पेज पर पहुंचते हैं और कोई दूसरी रकम देखते हैं।

इसी तरह, BookMyShow पर भी एक जानी-पहचानी ऑनलाइन आदत के लिए कार्रवाई की गई। मूवी-टिकट प्लेटफॉर्म को अपने BookASmile चैरिटी इनिशिएटिव के लिए पहले से टिक किए गए 1 रुपये के योगदान को हटाने का निर्देश दिया गया।

समस्या 1 रुपये की नहीं थी। समस्या यह थी कि योगदान पहले से ही चुना हुआ था यानी ग्राहक को उस पर ध्यान देना था और उसे हटाना था। सीसीपीए ने इसे बास्केट स्नीकिंग माना। चार टिकट बुक करने वाले व्यक्ति के लिए 1 रुपया मामूली लग सकता है लेकिन ठीक इसी वजह से ऐसी छोटी-छोटी चीजें ध्यान से छूट सकती हैं। इस बीच, IndiGo को कन्फर्म शेमिंग नाम की एक अलग तरकीब के लिए फटकार लगाई गई। एयरलाइन के एप में एक ऑप्ट-आउट मैसेज था जिसमें लिखा था, 'नहीं, मैं रिस्क लूंगा।'

ये एप्स कैसे करते थे खेला? अब उदारण के लिए जेप्टो को लेते हैं। सीसीपीए ने पाया कि ग्राहकों को शुरू में जो कीमतें दिखाई जाती थीं उन्हें बाद में हैंडलिंग चार्ज और मेंबरशिप फीस के जरिए बढ़ा दिया जाता था। रेगुलेटर ने हैंडलिंग चार्ज को ड्रिप प्राइसिंग माना जिसमें शुरुआती कीमत से यह पता नहीं चलता कि ग्राहक को आखिर में कितनी रकम चुकानी होगी।

दिल्ली सरकार में 650 करोड़ के खरीद घोटाले को लेकर प्रमुख सचिव को नोटिस जारी

● स्वास्थ्य मंत्री ने मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार में दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों के 650 करोड़ के खरीद घोटाले को लेकर जवाबदेही तय करने की कार्रवाई तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सरकार के तीन बार निर्देश देने के बावजूद लंबित खरीद प्रक्रियाओं की विस्तृत कार्ययोजना और कार्रवाई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। मंत्री ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

26 मई को दिया था पहला निर्देश: नोटिस के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग को 26 मई को सभी लंबित खरीद प्रक्रियाओं के लिए बिंदुवार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसमें दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद पूरी करने की समयसीमा तय करने के साथ सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से मांग भेजने की समयसीमा की समीक्षा भी शामिल थी।

दो अनुस्मारक के बाद भी नहीं मिला जवाब: सरकार का कहना है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर 17 जून और 22 जुलाई को फिर से अनुस्मारक भेजे गए। इसके बावजूद विभाग ने न तो अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई और न ही कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी।

नोटिस में बताई गंभीर प्रशासनिक लापरवाही: कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि तीन आधिकारिक पत्राचार के बावजूद आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे महत्वपूर्ण खरीद प्रक्रियाओं की निगरानी प्रभावित हुई और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना गया है।

जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों न हो कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रमुख सचिव से पूछा है कि सरकार के निर्देशों की अनदेखी क्यों की गई और कई अनुस्मारकों के बावजूद कार्रवाई रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि कथित कर्तव्यहीनता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए।

सीपीए खरीद मामले की जांच के बीच बढ़ी स ती

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब दिल्ली सरकार सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) के माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित रूप से कीमतें बढ़ाकर खरीद, निविदा शर्तों में हेरफेर और चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले ही वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका की जांच के आदेश दे चुकी हैं।

यूपी, बिहार में बदलेगा मौसम, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी; 19 राज्यों म IMD का अलर्ट

लखनऊ, पटना, एजेंसी। देश भर में मानसून ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मानसूनी ट्रफ और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में हालात सबसे ज्यादा संवेदनशील बने रहने की आशंका है, जहां कई पर्वतीय जिलों में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लगातार हो रही बारिश और भारतीय मौसम विभाग द्वारा राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने, संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने और नदियों और नालों में जलस्तर पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा दक्षिण और पश्चिमी भारत के केरल, कोंकण-गोवा, ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

दिल्ली-एनसीआर और यूपी-बिहार में भी बरसेगा पानी: राजधानी दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह से ही बादल छाए रहने और दिन भर रुक-रुक कर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा) में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

तेज हवाएं और मछुआरों के लिए चेतावनी

इस दौरान तटीय राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और उग्र मौसम को देखते हुए आईएमडी ने मछुआरों को गहरे पानी में न उतरने की सख्त सलाह दी है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और बिजली कड़कने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें।

उत्तराखंड सिलक्यारा हादसा: टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले 12 रैट माइनर्स को मिला वीरता पदक

देहरादून, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के नीचे फंसे श्रमिकों के बचाव में लगे 12 रैट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नवंबर 2023 में इन रैट माइनर्स ने 17 दिनों तक सुरंग के एक हिस्से में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में मदद की थी। 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग का खुदाई कार्य पिछले वर्ष अप्रैल में पूरा हुआ। इस डबल-लेन सुरंग से चार धाम मार्ग पर गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। पुरस्कार समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान को सबसे चुनौतीपूर्ण में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इस बचाव अभियान पर उच्चतम स्तर पर निरंतर ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटनाक्रम की निगरानी की और फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सभी संभव संसाधन जुटाने का आश्वासन दिया।

पाइपलाइन डालने से मिली सफलता

गडकरी ने कहा कि सुरंग के ढहे हुए हिस्से में पाइपलाइन डालने से एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिससे फंसे हुए श्रमिकों को भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। इन रैट माइनर्स ने स्वेच्छा से संकरे और खतरनाक स्थान में प्रवेश किया और मलबे को खुद हटाया जिससे सभी फंसे हुए श्रमिकों का सुरक्षित बचाव संभव हो सका।

असम में जेपी नड्डा का दौरा, बोले- असम में बाढ़ से हुआ भारी नुकसान, हालात सामान्य होने में लगेगा समय

गुवाहाटी, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि असम में बाढ़ से हुई तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि हालात सामान्य होने में समय लगेगा। इस बीच स्थिति और खराब हो गई है एवं राज्य में छह और लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या 95 हो गई है। साथ ही 14 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1.6 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने असम-नगालैंड सीमा पर स्थित शिवसागर जिले के नेपालीखुटी इलाके का दौरा किया। यह इलाका 19 जुलाई को आई बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। शाम को नड्डा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ की मौजूदा स्थिति और उसके बाद राहत, पुनर्वास एवं स्वास्थ्य देखभाल के उपायों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। प्रभावित लोगों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है।

पंजाब में बिजली व्यवस्था बदलेगी तस्वीर, 5 हजार करोड़ के काम शुरू; किसानों को आठ घंटे से ज्यादा आपूर्ति का दावा

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब सरकार ने रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपये के कार्य शुरू किए हैं। बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है।

उन्होंने दावा किया कि मई माह से किसानों को प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विधायक बलकार सिंह सिद्धू के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सौंद ने कहा कि आरडीएसएस के तहत पूरे प्रदेश में बिजली वितरण नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेटवर्क पर बढ़ते भार को कम करने और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अब तक 1,296 नए 11 केवी फीडर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए 1,12,195 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

बिजली नेटवर्क का विस्तार: बिजली मंत्री के अनुसार ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत 663 सर्किट किलोमीटर लंबी 66 केवी लाइनों का विस्तार और उन्नयन किया गया है, जबकि 355 सर्किट किलोमीटर नई 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। इससे बिजली आपूर्ति प्रणाली की क्षमता और संचालन दक्षता में सुधार होगा। बठिंडा क्षेत्र में चल रहे ट्रांसमिशन कार्यों का उल्लेख करते हुए सौंद ने बताया कि फूल और भाई रूपा के 66 केवी सब-स्टेशनों को फिलहाल 220 केवी गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट, लहरा मुहब्बत से आने वाली 66 केवी लाइन के माध्यम से बिजली आपूर्ति दी जा रही है। मौजूदा लाइन पर भार कम करने और आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए लहरा मुहब्बत से फूल सब-स्टेशन तक 13.2 सर्किट किलोमीटर लंबी नई समर्पित 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है।

बिजली आपूर्ति में सुधार और बुनियादी ढांचा

उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 11.08 सर्किट किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य में आठ ट्रांसमिशन टावरों का प्रतिस्थापन और चार क्रॉसिंग ढांचों की ऊंचाई बढ़ाना शामिल है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सौंद ने कहा कि अंतरिम व्यवस्था के तहत पीएसपीसीएल ने भाई रूपा, महराज और फूल के 66 केवी सब-स्टेशनों के बीच बिजली भार का संतुलन किया है। इससे मई माह से किसानों को प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार और घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में और सुधार होगा।

आम ग्राहकों के लिए ई-मेल के जरिए फंड ट्रांसफर की सुविधा बंद, सिर्फ इन लोगों को ही मिल सकेगा लाभ

लखनऊ, एजेंसी। बैंकों ने ग्राहकों (एनआरई -विदेशी मुद्रा के भारतीय खातों को छोड़कर) के लिए ई-मेल के आधार पर फंड ट्रांसफर की सुविधा बंद करने का फैसला किया है। कॉर्पोरेट ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए कई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य रहेंगे। बैंक अधिकारियों का कहना है कि साइबर धोखाधड़ी, फर्जी ई-मेल और दस्तावेजों के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नए निर्देशों के तहत, अब व्यक्तिगत ग्राहकों को धनराशि भेजने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआइ, एनईएफटी, आरटीजीएस या शाखा में जाकर निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। बैंक अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल माध्यमों में बहुस्तरीय प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) होने से लेनदेन अधिक सुरक्षित रहता है। अधिकारियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल को बैंक रिकॉर्ड में रखें, लेकिन किसी भी लेनदेन के लिए केवल अधिकृत डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करें। बैंकों ने स्पष्ट किया है कि कॉर्पोरेट संस्थाओं और एनआरई ग्राहकों के लिए ई-मेल या फैक्स (उपलब्धता पर) आधारित भुगतान सुविधा जारी रहेगी।

साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप का असर: बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में अपराधी अधिकारियों के नाम से नकली ई-मेल भेजकर करोड़ों का भुगतान अपने खातों में स्थानांतरित करा चुके हैं। ऐसे निर्णय आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।

गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक ट्रेन के चार अतिरिक्त फेरे बढ़े

गोरखपुर , एजेंसी। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 07075/07076 हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक विशेष ट्रेन के संचालन की अवधि चार अतिरिक्त फेरे बढ़ा दी है। रेलवे के अनुसार, 07075 हैदराबाद-गोरखपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन 4, 11, 18 और 25 सितंबर 2026 को हैदराबाद से चलेगी। वहीं 07076 गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक विशेष ट्रेन 6, 13, 20 और 27 सितंबर को गोरखपुर से रवाना होगी। रेल प्रशासन ने बताया कि विस्तारित अवधि में भी यह विशेष ट्रेन पहले से निर्धारित मार्ग, ठहराव, समय और रेक संरचना के अनुसार ही संचालित की जाएगी। इससे गोरखपुर और हैदराबाद के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

गोल्फ क्लब में सेंध: ट्रंप के अफसर बनकर घुसे संदिग्ध पर क्या आरोप लगे कार-घर से हथियार बरामद होने से हड़कंप

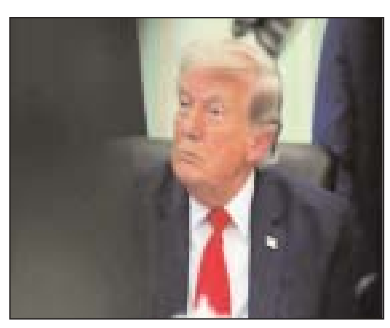

लॉस एंजिलिस, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैलिफोर्निया स्थित गोल्फ क्लब में सुरक्षा अधिकारी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को अवैध हथियारों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के वाहन और घर से कई हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान बरामद किया गया है।अधिकारियों के मुताबिक 38 वर्षीय जीनीन जॉन टाएले को रविवार को रैंचो पालोस वर्डेस स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब से गिरफ्तार किया गया। ट्रंप के फंडरेजिंग डिनर के लिए वहां पहुंचने से दो दिन पहले यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले शुक्रवार को भी गोल्फ क्लब परिसर में ईयरपीस पहनकर घूम रहा था और सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों की फोटो व वीडियो बना रहा था।क्या उसने खुद को स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी बताया था?अधिकारियों के अनुसार रविवार को दोबारा गोल्फ क्लब पहुंचने पर टाएले ने संघीय एजेंटों से कहा कि वह स्टेट डिपार्टमेंट में कार्यरत है और सुरक्षा ड्यूटी के लिए आया है। उसने यह भी बताया कि उसकी गाड़ी में लोडेड हथियार मौजूद है। वाहन की तलाशी लेने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 16 राउंड वाली मैगजीन और गोला-बारूद भी मिला।क्या आरोपी पर पहले से भी मामले दर्ज हैं?रिकॉर्ड के अनुसार टाएले पहले ही राज्य स्तर पर हथियार रखने के मामले और एक अलग घटना से जुड़े सेकेंड-डिग्री डकैती के आरोप में अदालत में पेश हो चुका है। फिलहाल वह राज्य के आरोपों में जेल में बंद है।क्या उसके घर से भी अवैध हथियार बरामद हुए?संघीय अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के घर की तलाशी में एक बिना पंजीकृत शॉर्ट-बैरल राइफल, अन्य हथियार, मैगजीन, गोला-बारूद, बॉडी आर्मर और नोटबुक बरामद हुईं। शिकायत में कहा गया है कि बरामद एआर-स्टाइल राइफल को अवैध रूप से संशोधित कर उसकी बैरल 14 इंच से घटाकर 10 इंच कर दी गई थी। लॉस एंजिलिस काउंटी शेरिफ विभाग के अनुसार गोल्फ क्लब की पार्किंग में खड़े आरोपी के पिकअप ट्रक से लोडेड 9 एमएम पिस्टल, दूरबीन और 'सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एजेंट' लिखा बैज बरामद किया गया।क्या एफबीआई ने इसे गंभीर सुरक्षा मामला बताया?एफबीआई के लॉस एंजिलिस कार्यालय के सहायक निदेशक पैट्रिक ग्रैंडी ने कहा। ।कि राष्ट्रपति के सार्वजनिक गोल्फ क्लब में उनके पहुंचने से कुछ दिन पहले आरोपी का व्यवहार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर पहले हो चुके हमलों को देखते हुए किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं है।

क्या ट्रंप ने गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी: फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि केवल प्रभावशाली राष्ट्रपतियों को ही निशाना बनाया जाता है और वह खुद को निश्चित रूप से ऐसा राष्ट्रपति मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस सोच से उन्हें कुछ संतोष मिलता है।

क्या आरोपी अमेरिकी मरीन में भी रह चुका है: जानकारी के अनुसार टाएले 2008 से 2016 तक अमेरिकी मरीन में कॉर्पोरल रहा था। इस दौरान उसकी तैनाती इराक और अफगानिस्तान में भी हुई थी। सेवा के दौरान उसे अच्छे आचरण सहित कई सम्मान भी मिले। राज्य के रिकॉर्ड बताते हैं कि वह लाइसेंस प्राप्त सुरक्षा गार्ड है, हालांकि सुरक्षा गार्ड के रूप में हथियार रखने से जुड़े उसके कई परमिट रद्द या निलंबित किए जा चुके हैं।

मोजतबा से संपर्क करना मुश्किल: सत्ता संघर्ष के बीच बोले ईरानी राष्ट्रपति, पेजेश्कियन के इस बयान मायने क्या

नॉर्थ केरोलिना, एजेंसी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के कैसवेल काउंटी में बुधवार सुबह एक घर में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हैं।

नॉर्थ कैरोलिना स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 8 बजे (स्थानीय समय) पुलिस को एक घर में गोलीबारी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और शेरिफ कार्यालय की टीम मौके पर पहुंची। वहां कई लोग गोली लगने से घायल मिले। घायलों में से एक व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कई अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कैसवेल काउंटी के शेरिफ टोनी डर्डन ने बताया कि मृतकों में एक संदिग्ध हमलावर भी शामिल है। कुल तीन परिवार के सदस्यों की मौत हुई है, जबकि एक अन्य रिश्तेदार घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। हालांकि, गोलीबारी की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है।अमेरिका में लगातार बढ़ रही गोलीबारी की घटनाएंअमेरिका में बंदूक हिंसा लंबे समय से गंभीर समस्या बनी हुई है। हर साल देश में सैकड़ों सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं सामने आती हैं।

ईरान-ओमान ने समझौते का मसौदा तैयार किया, खामेनेई की अंतिम मंजूरी का इंतजार; अमेरिका का रूख क्या

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में 160 दिनों से शांति बहाली का इंतजार हो रहा है। अमेरिका-इस्राइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग शुरू की थी। इस्लामाबाद में समझौते के बाद दोनों देशों के बीच करीब दो हफ्ते की शांति रही। टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दोनों देशों के बीच समझौता कब होगा? पश्चिम एशिया और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर तनावपूर्ण हालात कब सामान्य होंगेईरान के साथ समझौते के लिए क्यों राजी हुआ अमेरिका , ईरान-ओमान ने जंग खत्म करने को लेकर समझौते का मसौदा तैयार किया है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले इस समझौते को अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इस डील के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। ट्रंप ने भी डील के संबंध में बड़ा बयान दिया है। दरअसल, लंबे समय से जारी जंग के बीच अमेरिका में हथियारों की कमी को लेकर पेंटागन के अलावा कई स्तरों पर चिंता जताई जा चुकी है। कई अमेरिकी सैनिक भी हताहत हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आर्थिक और सैन्य नुकसान जैसे तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ईरान के साथ समझौते को प्राथमिकता दे रहे हैं ट्रंप समझौते पर 48 घंटे का जिक्र कर क्या बोले? इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर इस सप्ताह समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है और घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। इस बीच ईरान और ओमान के वार्ताकारों ने समझौते का मसौदा तैयार कर लिया है। अब इसे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अधिकारियों के अनुसार, यह समझौता फिलहाल अस्थायी होगा और इसके बाद अमेरिका तथा ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। पांच महीने से जंग, शांति बहाली पर ईरान का रूख क्या? रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और इस्राइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद संघर्ष होर्मुज जलडमरूमध्य तक पहुंच गया। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि वह ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा, जिससे ईरान को इस जलमार्ग पर नियंत्रण मिल जाए या वह जहाजों से शुल्क वसूले। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में है और यदि कोई बाधा नहीं आई तो जल्द संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। बेहद अहम समुद्री मार्ग है होर्मुज जलडमरूमध्य होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। युद्ध से पहले दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती थी। संघर्ष के दौरान इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई, जिससे तेल और जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। लाल सागर में जहाजों पर हमले जारी होर्मुज जलडमरूमध्य पर समझौते की उम्मीद के बीच लाल सागर में जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने यनबू बंदरगाह के पास सऊदी अरब के एक तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, इसका कोई सबूत नहीं दिया गया और सऊदी अरब ने भी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले जुलाई में हूतियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों के लिए बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य बंद करने की घोषणा की थी।

पीएम पोषण योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर, स्व-सहायता समूहों को दिए गए सख्त निर्देश

बच्चों को मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश, लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर विकास मिश्रा के कुसमी भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बीआरसीसी अंगिरा प्रसाद द्विवेदी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी मानकुमारी पनाडिया ने स्व-सहायता समूहों के अध्यक्षों एवं सचिवों की विशेष बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए बैठक का मुख्य उद्देश्य शासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित पीएम पोषण योजना की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भोजन की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए बैठक में निर्देश दिए गए कि बच्चों को प्रतिदिन शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन तैयार करने से लेकर वितरण तक स्वच्छता के सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। बच्चों को भोजन से पहले साबुन से हाथ धुलवाने, उन्हें व्यवस्थित तरीके से बैठाकर भोजन कराने और प्रत्येक बच्चे को निर्धारित मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में भोजन वितरण के समय एक शिक्षक की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी संबंधित शिक्षक बच्चों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे और भोजन की गुणवत्ता मात्रा तथा वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी स्व-सहायता समूहों के अध्यक्ष और सचिवों को भी नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि बच्चों को निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन मिल रहा है या नहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यालय या केंद्र में भोजन की गुणवत्ता अथवा व्यवस्था में कमी पाई जाती है तो संबंधित समूह के अध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी तय की जाएगी बैठक में पीएम पोषण योजना के तहत उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए अधिकारियों ने कहा कि प्राप्त राशि से आवश्यक रसोई सामग्री और बर्तनों की खरीदी कर उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किया जाए इसके साथ ही उपलब्ध प्रेशर कुकरों की नियमित जांच कर आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाए खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के लिए दो माह का खाद्यान्न एक साथ उठाव करने के निर्देश भी दिए गए अधिकारियों ने भोजन व्यवस्था में रिकॉर्ड संधारण को भी महत्वपूर्ण बताया निर्देश दिए गए कि प्रतिदिन विद्यालय में तैयार किए गए भोजन का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इसमें क्या बना कितनी मात्रा में बना और कितने बच्चों ने भोजन किया इसकी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा साथ ही रसोइया के हस्ताक्षर भी नियमित रूप से लिए जाएं योजना में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक स्व-सहायता समूह और रसोइया का संबंधित पोर्टल पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए इसके अलावा प्रतिदिन भोजन करते हुए बच्चों की फोटो पीएम पोषण व्हाट्सऐप समूह में साझा करने को कहा गया ताकि योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति की निगरानी की जा सके बैठक में अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य केवल बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना नहीं है बल्कि उनके स्वास्थ्य, पोषण स्तर स्वच्छता और नियमित विद्यालय उपस्थिति को बढ़ावा देना भी है इसलिए सभी संबंधित अधिकारी शिक्षक स्व-सहायता समूह और रसोइया पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

स्व-सहायता समूह से जुड़कर उर्मिला सोंधिया बनीं आत्मनिर्भर महिला उद्यमी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य कर रहा है जिले के सीधी विकासखंड अंतर्गत ग्राम जोगीपुर की निवासी उर्मिला सोंधिया इसकी प्रेरणादायी मिसाल हैं स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि स्वरोजगार स्थापित कर अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हैं वर्ष 2018 में उर्मिला सोंधिया आशा स्व-सहायता समूह से जुड़ीं।उस समय उनका परिवार मुख्य रूप से कृषि कार्य पर निर्भर था और सीमित आय के कारण परिवार का भरण-पोषण कठिनाई से हो पाता था गांव में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की जानकारी मिलने पर उन्होंने समूह की सदस्यता ग्रहण की और नियमित बचत एवं बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया समूह को प्राप्त चक्रीय निधि (आरएफ) से मिली आर्थिक सहायता का उपयोग उर्मिला ने इलेक्ट्रॉनिक एवं रेफ्रिजरेशन कार्य की शुरुआत करने में किया। मेहनत और लगन से उन्होंने एयर कंडीशनर की बिक्री एवं सर्विसिंग का कार्य शुरू किया। व्यवसाय से आय बढ़ने पर उन्होंने समय पर समूह की राशि वापस कर दी इसके बाद समूह को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में 50 हजार रुपये प्राप्त हुए इस सहायता से उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया, आवश्यक उपकरण खरीदे तथा ए.सी. से संबंधित कार्य को बड़े स्तर पर विकसित किया बढ़ती आमदनी के साथ उन्होंने सीआईएफ की राशि भी समय पर समूह को लौटा दी बाद में समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से 50 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि का उपयोग कर उर्मिला ने अपने गांव में सिलाई कार्य एवं सिलाई केंद्र भी प्रारंभ किया। वर्तमान में वे इलेक्ट्रॉनिक एवं ए.सी. व्यवसाय के साथ सिलाई कार्य से भी नियमित आय अर्जित कर रही हैं इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है वे नियमित बचत कर रही हैं तथा अपने सभी ऋणों का समय पर भुगतान भी कर चुकी हैं उर्मिला सोंधिया का कहना है कि स्व-सहायता समूह ने उन्हें केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान किया वे अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

कांग्रेस सेवादल की जिला समीक्षा बैठक सम्पन्न, संगठन विस्तार पर मंथन

प्रदेश प्रभारी प्रताप नारायण मिश्रा ने पदाधिकारियों को दिए सक्रियता, अनुशासन और एकजुटता के मंत्र

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कांग्रेस सेवादल जिला रीवा की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, बजरंग नगर (उर्रहट) में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस सेवादल के प्रदेश प्रभारी प्रताप नारायण मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए इस दौरान जिले के विभिन्न ब्लॉक मंडलम शहर एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों ने निर्धारित वर्दी में उपस्थित होकर संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने को लेकर विचार-विमर्श किया बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस सेवादल के जिला ग्रामीण अध्यक्ष अनिल तिवारी एवं शहर अध्यक्ष आनंद कुशवाहा ने पदाधिकारियों का स्वागत किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवादल पार्टी की विचारधारा अनुशासन और संगठनात्मक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे ब्लॉक और मंडलम स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करें मुख्य अतिथि प्रताप नारायण मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सेवादल केवल एक संगठन नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और समर्पण की पहचान है उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक संगठन का विस्तार करने तथा कांग्रेस की नीतियों एवं जनहित के मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही भविष्य की राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर सकता है इसके लिए प्रत्येक पदाधिकारी को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहना होगा बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति, सदस्यता अभियान, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और ब्लॉक एवं मंडलम स्तर पर कार्ययोजना की समीक्षा की गई पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों की गतिविधियों की जानकारी साझा करते हुए संगठन विस्तार के लिए सुझाव भी दिए इस अवसर पर जिला ग्रामीण अध्यक्ष अनिल तिवारी, शहर अध्यक्ष आनंद कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे बैठक के अंत में पदाधिकारियों ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

दस्तक अभियान की मॉनिटरिंग के लिए बढ़ौरा उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर स्वास्थ्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में संचालित दस्तक अभियान एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. नागेंद्र बिहारी दुबे तथा कार्यालयीन लिपिक प्रकाश कुमार पांडे ने विकासखंड सीधी अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़ौरा का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अवकाश पर थीं, जबकि एएनएम पॉलीक्सीना मिश्रा एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कपिल मुनि पांडे केंद्र में उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों एवं माइक्रोप्लान का परीक्षण किया गया। माइक्रोप्लान के अनुसार टीकाकरण दिवस के अतिरिक्त अन्य दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दस्तक अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में भ्रमण कर घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एवं अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना निर्धारित है। इसके बावजूद दोनों स्वास्थ्य कर्मी केंद्र में उपस्थित पाए गए इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खरे ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना दस्तक अभियान की मूल भावना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की। अभिलेखों के आधार पर दल ने निकटवर्ती समुदाय में विश्वकर्मा परिवार के घर पहुंचकर प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का भौतिक सत्यापन किया तथा हितग्राहियों से चर्चा कर सेवाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने कहा कि दस्तक अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है इसके लिए सभी मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों का नियमित क्षेत्र भ्रमण आवश्यक है उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी अपने निर्धारित क्षेत्र में जाकर सेवाएं प्रदान करें तथा सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें उन्होंने बताया कि जिले में दस्तक अभियान सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सघन मॉनिटरिंग निरंतर जारी रहेगी तथा कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बारिश से सेमरिया तहसील कार्यालय में जलभराव, दूसरे दिन भी नहीं पहुंचे तहसीलदार कामकाज प्रभावित, दूर-दराज से आए लोगों को बिना काम लौटना पड़ा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है गुरुवार सुबह हुई तेज बारिश के कारण सेमरिया तहसील कार्यालय परिसर में जलभराव हो गया जिससे कार्यालय का नियमित संचालन प्रभावित रहा वहीं प्रभारी तहसीलदार के लगातार दूसरे दिन अनुपस्थित रहने से राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा जानकारी के अनुसार, सेमरिया तहसील कार्यालय वर्तमान में ग्राम पंचायत भवन में संचालित किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते भवन और परिसर में पानी भर गया जिससे कार्यालय के भीतर कामकाज करना मुश्किल हो गया पेशी नामांतरण प्रमाण-पत्र और अन्य राजस्व कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों के नहीं पहुंचने से उन्हें बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि गुरुवार को प्रभारी तहसीलदार आशीष द्विवेदी कार्यालय नहीं पहुंचे। कर्मचारियों के अनुसार, बुधवार को भी वे अनुपस्थित रहे थे। लगातार दूसरे दिन कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहने से लोगों में नाराजगी देखी गई स्थानीय निवासी रविंद्र तिवारी ने बताया कि तहसील से जुड़े छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी उन्हें बार-बार जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं ऐसे में तहसील स्तर पर अधिकारी उपलब्ध नहीं रहने से आम नागरिकों की परेशानी और बढ़ जाती है उनका कहना है कि जिला मुख्यालय तक आने-जाने में समय और अतिरिक्त खर्च दोनों का सामना करना पड़ता है वहीं प्रभारी तहसीलदार आशीष द्विवेदी ने बताया कि भारी बारिश और जलभराव के कारण वे कार्यालय नहीं पहुंच सके उन्होंने कहा कि जिन लोगों के अत्यावश्यक कार्य हैं वे जिला कार्यालय पहुंचकर उनका निराकरण करा सकते हैं हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य ही लोगों को जिला मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर से बचाना है ऐसे में बारिश के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

एक साल में जर्जर हुई गोड़ी-चितरासी सड़क, ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल बारिश में गड्ढों से बढ़ा हादसे का खतरा, जांच के आदेश जल्द मरम्मत का आश्वासन

मीडिया ऑडीटर, शहडोल, (निप्र)। ब्यौहारी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कुआं की गोड़ी-चितरासी सड़क निर्माण के महज एक वर्ष बाद ही जर्जर हो गई है सड़क कई स्थानों पर उखड़ चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने से ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरपंच पर लापरवाही का आरोप लगाया है तथा मामले की तकनीकी जांच की मांग की है ग्रामीणों के अनुसार, यह सड़क गांव का प्रमुख संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से छात्र-छात्राएं स्कूल जाते हैं, किसान खेतों तक पहुंचते हैं और ग्रामीण दैनिक कार्यों के लिए आवाजाही करते हैं सड़क की बदहाल स्थिति के कारण दोपहिया वाहन चालकों बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया उनका कहना है कि निर्माण के कुछ ही महीनों बाद सड़क की परत उखड़ने लगी थी लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई अब सड़क कई हिस्सों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और यदि अनियमितता या लापरवाही सामने आए तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है साथ ही सड़क की तत्काल मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की अपील की है वार्ड पंच ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) कल्पना यादव ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच के साथ ही सड़क की शीघ्र मरम्मत कराई जाएगी ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।

उपखंड अधिकारी प्रिया पाठक ने आंगनवाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, बच्चों की उपस्थिति एवं पोषण सेवाओं पर दिया जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। उपखंड अधिकारी गोपद बनास प्रिया पाठक ने परियोजना सीधी क्रमांक-2 अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पटेहरा कला-1 एवं पटेहरा कला-2 का औचक निरीक्षण कर केंद्रों के संचालन एवं विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ममता सिंह तथा पर्यवेक्षक ललिता गुप्ता ने केंद्रों के संचालन, विभागीय गतिविधियों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उपखंड अधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों से संपर्क बनाए रखने पर बल दिया उन्होंने साझा चूल्हा योजना के अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे नाश्ता एवं गर्म भोजन की व्यवस्था का अवलोकन कर गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी, समय पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया उपखंड अधिकारी ने गंभीर कुपोषित (सैम) एवं मध्यम कुपोषित (मैम) बच्चों की पहचान कर आवश्यकतानुसार उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

CMHO के औचक निरीक्षण में चुरहट अस्पताल की खुली पोल

प्रभारी डॉक्टर समेत कई कर्मचारी मिले नदारद, दवा संकट और गंदगी पर जताई नाराजगी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत बुधवार को उस समय सामने आई, जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. स्मृति शुक्ला ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. वरुण सिंह सहित कई कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर CMHO ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के संकेत दिए हैं जानकारी के अनुसार, CMHO स्मृति शुक्ला ने सुबह करीब 10:30 बजे जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) अखिलेश सोनी और बीसीएम के साथ चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें कई खामियां सामने आईं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के साथ ही दवाओं की कमी और साफ-सफाई व्यवस्था में लापरवाही भी सामने आई। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर CMHO ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए CMHO ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. वरुण सिंह लगातार अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरत रहे हैं। इससे पहले भी निरीक्षण के दौरान वह बिना सूचना के कई दिनों तक अनुपस्थित पाए गए थे। संयुक्त संचालक (JD) रीवा के निरीक्षण में भी उनकी अनुपस्थिति सामने आई थी। इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं अस्पताल पहुंचे मरीजों और स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने बताया कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति, आवश्यक दवाओं की कमी और अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता कई बार मजबूरी में मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है CMHO ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण

संपादकीय

यह जरूरी है कि देश में जन्म व मृत्यु से जुड़े आंकड़े प्रामाणिक हों और समय रहते दर्ज कर लिए जाएं। इससे जनसंख्या गणना, मतदाता की विश्वसनीयता और अंततः विकास योजनाओं के लिये विश्वसनीय आंकड़े जुटा पाना संभव होता है। वहीं दूसरी ओर अवैध घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों की पहचान भी संभव हो पाती है। जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसी आलोक में संसद द्वारा हाल ही में 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण(संशोधन) विधेयक' को पारित करना, देश की नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल, यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि जन्म व मृत्यु का पंजीकरण समय रहते कर लिया जाए। यह कानून देर से होने वाले पंजीकरण के लिए सख्त नियम लागू करता है। नये संशोधन के तहत, जन्म व मृत्यु के दो साल बाद रिपोर्ट किए गए मामलों में मौजूदा कार्यकारी मंजूरी की जगह अब प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। निस्संदेह, फर्जी पंजीकरण को रोकने की दिशा में सरकार का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन यह संशोधन लोगों की पहुंच और समावेशिता के बाबत कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। निस्संदेह, आज देश ने सिविल रजिस्ट्रेशन यानी जन्म-मृत्यु पंजीकरण के मामलों में बहुत अच्छी प्रगति की है। आज देश में 99 फीसदी से अधिक जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखा जाता है। दरअसल, देश में बड़ी चुनौती सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि जन्म व मृत्यु होने पर 21 दिन के भीतर सूचना दर्ज कर ली जाए। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रक्रियागत बाधाएं बढ़ाने की बजाय, समय पर रिपोर्टिंग करने को सहज व सरल बनाया जाए। लोगों को इस बाबत जागरूक करने की भी जरूरत है। साथ ही मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने से अधिक नीतिगत मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार का दावा है कि न्यायिक जांच से पंजीकरण में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगायी जा सकेगी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि वर्ष 2023 संशोधनों के तहत कई सरकारी सेवाओं के लिये जन्म प्रमाण पत्र पहचान का मुख्य दस्तावेज बन गया है। हालांकि, इस बाबत दो साल की समय-सीमा चुनने के पीछे की वजह को तार्किक आधार पर नहीं बताया गया है। वहीं कई ऐसे वाजिब कारण हैं जिसके चलते पंजीकरण देर से होता है। उदाहरण के लिये लें तो दूरदराज के इलाकों में जन्म, पलायन और जागरूकता की कमी के कारण भी जन्म-मृत्यु के पंजीकरण में विलंब होता है। लेकिन अब नये कानून से प्रभावित परिवारों के लिये खर्च और देरी, दोनों ही बढ़ सकते हैं। यह विडंबना ही है कि यह बिल संसद के दोनों सदनों में जारी लगातार हंगामे के बीच पास हुआ। जिसकी वजह से इस महत्वपूर्ण बिल पर कोई सार्थक बहस नहीं हो सकी। वास्तव में होना तो यह चाहिए था कि हर नागरिक की कानूनी पहचान को प्रभावित करने वाले कानून की गहनता से पड़ताल की जाती। जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। निस्संदेह, कुशल प्रशासन में कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने और चुनावी ईमानदारी के लिये एक मजबूत व पारदर्शी नागरिक पंजीकरण प्रणाली अपरिहार्य ही है। वास्तव में इस संशोधन की प्रभावशीलता को सिर्फ धोखाधड़ी रोकने की क्षमता से नहीं देखा जाना चाहिए। सावधानी इस बात को लेकर भी की जानी चाहिए कि कोई भी वास्तविक नागरिक कानूनी पहचान से वंचित न रह जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सुरक्षा उपाय नागरिकों की पहुंच में बाधा नहीं बनने चाहिए। सही मायने में अच्छी गवर्नेंस, प्रशासनिक ईमानदारी और लोगों के अधिकारों, दोनों को ही सुरक्षित रखने में है।

प्रशांत किशोर की जीत से या बदलेगी बिहार की सियासत

राधा रमण

प्रशांत किशोर ने पटना के बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव में वह करिश्मा कर दिखाया, जिसकी बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों को उम्मीद नहीं थी। बांकीपुर का चुनाव परिणाम महज एक विधानसभा का चुनावी नतीजा नहीं माना जाना चाहिए। यह विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई वह सीट है, जिस पर नितिन नवीन और उनके स्वर्गीय पिता नवीन किशोर सिन्हा का पिछले 30 वर्षों से कब्जा था। प्रशांत किशोर ने महज 30 दिनों की मेहनत से बड़ा उलटफेर कर दिया। यह सब अचानक नहीं हुआ। बेशक, इसके लिए प्रशांत किशोर को अपना सौ प्रतिशत देना पड़ा। सनद रहे कि पानी सौ डिग्री पर उबालने पर ही वाष्प बनता है। नौ महीने पहले बिहार विधानसभा के चुनाव में जनसुराज के 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी थी। महज दो उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाए थे। हालांकि तब भी जनसुराज को 3.4 फीसदी वोट जरूर मिले थे। किसी नयी-नवेली पार्टी के लिए यह कम नहीं है। राजनीति के जानकार भी यह समझ नहीं सके। उधर, जनसुराज की करारी हार से पक्ष-विपक्ष दोनों खुश थे। जनसुराज ने अपना कोर मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पलायन को ही बनाया था। आज भी जनसुराज से जुड़े लोग उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं।

बांकीपुर के कुल मतों का आधा प्रशांत को मिला

बांकीपुर उपचुनाव में इस बार सबसे कम मतदान हुआ था। 3 लाख 79 हजार मतदाताओं वाले बांकीपुर में इस बार महज 1,30,246 लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें से 64,151 मत अकेले प्रशांत को मिले। भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा गुप्ता को 14,273 मत मिले। शेष बचे 22 उम्मीदवारों में से प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन श्रीवास्तव को सबसे अधिक 973 तो निर्दलीय ब्रजेश पटेल को सबसे कम महज 70 वोट मिले। 646 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया।

प्रशांत के फतह के पीछे की कहानी

2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रशांत हताश होकर घर नहीं बैठे। वह पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम पहुंचे, जहां से गांधीजी ने अंग्रेजों के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने 24 घटे का मौन व्रत किया फिर कहा कि वह लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बिहार में घर-घर तक जाएंगे। जनसुराज की लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि बिहार बदलने की है। बिहार में खुशहाली लाना ही उनका ध्येय है। उन्होंने अपने जीवन का 10 साल बिहार के विकास के लिए समर्पित करने का फैसला किया है। उन्होंने दिल्ली का अपना आवास छोड़कर अपने 20 वर्षों की अर्जित कमाई का 90 फीसदी जनसुराज को दान कर दिया। कहा, आगे भी वह जो कमाएंगे, उसका 90 फीसदी जनसुराज का होगा। उन्होंने लोगों से भी कम से कम 1000 रुपये जनसुराज को दान करने की अपील की। बाद के दिनों में लोगों ने देखा कि चाहे पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला हो, पटना के ही बंटी यादव की हत्या अथवा आरा के बेलौटी गांव के भारत भूषण तिवारी की हिरासत में लेकर हत्या, प्रशांत किशोर हर जगह पहुंचे और पीड़ितों के आंसू पोंछे। पटना में पिछले माह छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ उन्होंने हुंकार भरी। जबकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की हार से इतने हताश हुए कि विधानसभा की बैठकों में भी कम ही जाते हैं। इसका सीधा लाभ बांकीपुर के उप चुनाव में प्रशांत किशोर को मिला। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के पास पेड वर्करों का भारी जमावड़ा था। इस बार बांकीपुर में प्रशांत ने समर्पित कार्यकर्ताओं को साथ लिया। इनमें अधिकांश युवा थे जो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे।

सीजेपी प्रेशर-ग्रुप ही बनी रहेगी या फिर राजनीति में भी उतरेगी

राजदीप सरदेसाई

कभी-कभार असंभव लगने वाली कहानियां भी रहस्यमयी रूप से सच हो जाती हैं। हर दिन करोड़ों लोग सिस्टम को बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम सफल हो पाते हैं। इसीलिए 30 वर्षीय अभिजीत दिपके के अप्रत्याशित उभार को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसने सोचा होगा कि 16 मई को 'कॉकरोचों' से एकजुट होने की अपील करने वाला उनका एक ट्वीट युवाओं के देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाएगा और अंततः एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा? कुछ समय पहले तक दिपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को देश में शायद ही कोई जानता था। आज हालात ये हैं कि टीवी चैनलों की टीमें, यूट्यूबर और बड़े राजनेता उनके सम्भाजीनगर स्थित साधारण से घर का रास्ता तलाश रहे हैं। जिसे बहुत-से लोगों ने महज ऑनलाइन ट्रेंड समझकर खारिज कर दिया था, अचानक वह साल की सबसे बड़ी सियासी खबरों में से एक बन गया। बहरहाल, सीजेपी ने तात्कालिक लड़ाई भले जीत ली हो, उसकी असल चुनौती अब शुरू होती है। क्या सीजेपी को महज एक प्रेशर-ग्रुप बने रहना चाहिए, या वह चुनावी राजनीति में भी उतरेगी? हाल ही में मैंने यही सवाल दिपके से पूछा। उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि 'हमने राजनीतिक दल बनाने के बारे में सोचा तक नहीं है। हम ऐसा आंदोलन बने रहना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में जवाबदेही की मांग करता हो।' देश ने पहले भी यह बात सुनी है। 2011 में अरविंद केजरीवाल बार-बार कहते रहे थे कि उनकी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है, लेकिन महज दो साल बाद वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। हर सफल प्रतिरोध-आंदोलन अंततः इसी उलझन में फंस जाता है- नैतिक शक्ति को राजनीतिक ताकत में कैसे बदला जाए, बगैर उस साख को खोए, जिसने वह नैतिक शक्ति दी थी? इस उलझन को दिपके बहुत-से लोगों से बेहतर समझते हैं। चूंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था, इसलिए वे कहानी के दोनों पहलू देख चुके थे।

'आप' ने साबित किया कि जनता की नाराजगी को चुनावी सफलता में बदला जा सकता है। लेकिन उसने यह भी दिखाया कि जब कोई आंदोलन प्रतिस्पर्धी राजनीति की कठोर दुनिया में प्रवेश करता है- जहां गठबंधन, समझौते और संगठनात्मक मजबूरियां अपरिहार्य हो जाती हैं- तब उसकी नैतिक शुचिता बनाए रखना कितना कठिन हो जाता है। इतिहास बताता है कि हर सफल राजनीतिक बदलाव के लिए जनाक्रोश से अधिक भी कुछ चाहिए होता है। उसके लिए सही टाइमिंग और एक स्पष्ट सामाजिक आधार जरूरी होता है। केजरीवाल केवल भ्रष्टाचार-विरोधी लहर पर सवार नहीं हुए थे। वे भारत के बढ़ते शहरी मध्यम वर्ग की आवाज बने थे। यह वो पढ़ा-लिखा वर्ग था, जो भ्रष्टाचार, बदतर सार्वजनिक सेवाओं और आमजन की चिंताओं से कटे हुए तंत्र से हताश था। यही वर्ग 'आप' की मजबूत नींव बना। हर सफल राजनीतिक स्टार्टअप को ऐसा ही नैसर्गिक समर्थन-आधार चाहिए होता है। नैतिक आक्रोश किसी आंदोलन को जन्म तो दे सकता है, लेकिन चुनाव में शायद ही टिक पाता है। यही बात हमें उस सवाल तक ले आती है, जिसका सामना दिपके कर रहे हैं। आखिर सीजेपी का प्रमुख समर्थक वर्ग कौन है? क्या वह बार-बार पेपर लीक से परेशान जेन-जी है? नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे बेरोजगार स्नातक हैं? या वो महत्वाकांक्षी निम्न-मध्यम वर्ग है, जो सोचता है कि उसे भारत की विकास-यात्रा में अलग-थलग कर दिया गया है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, किसी आंदोलन का चुनावी ताकत में बदल पाना बेहद कठिन होगा। भाजपा आज भी देश की सबसे प्रभावशाली चुनावी ताकत है।

एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा करवा देना यकीनन बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भाजपा जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी को मात दे पाना बिल्कुल अलग बात है। दरअसल, सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत इसी तथ्य में निहित है कि वह राजनीतिक दल नहीं है। इस आंदोलन ने जनता के दिल में जगह इसीलिए बनाई, क्योंकि यह पारंपरिक दलगत राजनीति से ऊपर था। इसने युवाओं को अपनी नाराजगी व्यक्त करने का एक मंच दिया। यह नैतिक विश्वसनीयता बेहद कीमती है। एक बार गंवा दी तो शायद ही कभी वापस मिल पाए। जैसे ही कोई आंदोलन चुनावी राजनीति में प्रवेश करता है, उसका हर निर्णय किसी समझौते जैसा हो जाता है। जो संगठन कभी बाहर से व्यवस्था को चुनौती देता था, धीरे-धीरे उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। शायद इसीलिए सीजेपी प्रेशर ग्रुप ही बने रहना चाहती है।

परंपरा और संविधान के बीच संतुलन तलाशता समाज

डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा के जींद जिले में नौगामा खाप की महापंचायत द्वारा प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों के 21 गांवों में प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी कथित निर्णय ने एक बार फिर उस बहस को जीवित कर दिया है, जो समय-समय पर भारतीय समाज के सामने खड़ी होती रही है- क्या सामाजिक परंपराएं किसी बालिग नागरिक के संवैधानिक अधिकारों से ऊपर हो सकती हैं? यह विवाद केवल एक पंचायत या एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि बदलते भारतीय समाज, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं के बीच संतुलन की चुनौती को भी सामने लाता है।

खाप पंचायतों का इतिहास सदियों पुराना है। ग्रामीण समाज में उन्होंने विवाद निपटाने, सामाजिक अनुशासन बनाए रखने और सामुदायिक सहयोग को मजबूत करने का कार्य किया है। अनेक अवसरों पर जल संरक्षण, नशामुक्ति, सामाजिक समरसता और सामूहिक हितों से जुड़े निर्णयों में उनकी सकारात्मक भूमिका रही है इसलिए उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। किंतु जब कोई निर्णय संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता दिखाई देता है, तब उस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारतीय संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय भी अनेक निर्णयों में स्पष्ट कर चुका है कि दो वयस्कों का सहमति से किया गया विवाह कानून की दृष्टि में पूरी तरह वैध है। ऐसी स्थिति में किसी सामाजिक संस्था द्वारा ऐसे विवाहों पर रोक लगाने या सामाजिक बहिष्कार की घोषणा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक युवती का वीडियो चर्चा का केंद्र बन गया। उसने एक ऐसा सवाल उठाया, जिसे केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया कहकर टाला नहीं जा सकता।

उसका प्रश्न था कि जब हरियाणा में वर्षों तक कन्या भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्या कम होती रही और अनेक परिवार दूसरे राज्यों से महिलाओं को खरीद कर विवाह करने लगे, तब समाज की सामूहिक चेतना उतनी मुखर क्यों नहीं दिखाई दी? यदि सहमति से किया गया प्रेम विवाह सामाजिक संकट माना जाता है तो मानव तस्करी जैसी अमानवीय प्रवृत्तियों पर समान कठोरता क्यों नहीं दिखाई जाती? यह प्रश्न केवल खाप पंचायतों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और बेटियों के प्रति भेदभाव जैसे अनेक सामाजिक संकट आज भी हमारे सामने हैं। यदि समाज की सामूहिक शक्ति इन समस्याओं के समाधान में अधिक सक्रिय हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होगा। यह भी सत्य है कि हर प्रेम विवाह सफल नहीं होता। कई बार जल्दबाजी, अपरिपक्व निर्णय या पारिवारिक संवाद की कमी से रिश्तों में तनाव पैदा होता है। माता-पिता की चिंताएं भी कई बार वास्तविक होती हैं। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने निर्णय परिपक्वता, पारदर्शिता और परिवार के सम्मान को ध्यान में रखकर लें। संवाद हमेशा टकराव से बेहतर विकल्प होता है। उधर, सामाजिक संस्थाओं को भी यह स्वीकार करना होगा कि बदलते समय में अधिकारों और स्वतंत्रताओं की नई समझ विकसित हुई है। परंपराओं का सम्मान आवश्यक है किंतु वे तभी टिकाऊ होती हैं जब वे न्याय, समानता और मानव गरिमा के साथ सामंजस्य स्थापित करें।

समाज की भूमिका भय पैदा करने की नहीं, विश्वास बनाने की होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पक्ष प्रतिनिधित्व का है। जिन निर्णयों का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? क्या सामाजिक निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्गों की पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित है? लोकतांत्रिक समाज में यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परंपरा और अधिकार का प्रश्न। आज का भारत तेजी से बदल रहा है। शिक्षा, रोजगार, तकनीक और संचार ने नई पीढ़ी की सोच को नया आयाम दिया है। ऐसे समय में सामाजिक संस्थाओं के सामने चुनौती यह है कि वे अपनी ऐतिहासिक भूमिका को बनाए रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ तालमेल बैठाएं। संवाद, समझ और सहमति का मार्ग ही समाज को आगे ले जा सकता है। दरअसल, यह विवाद प्रेम विवाह बनाम परंपरा का नहीं बल्कि समाज की प्राथमिकताओं का है। यदि हम कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, महिला सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर उतनी ही गंभीरता से एकजुट हों, जितनी व्यक्तिगत निर्णयों पर दिखाई देती है तो समाज अधिक स्वस्थ और संतुलित बन सकता है। लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि वह परंपराओं का सम्मान करते हुए भी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए आवश्यकता किसी पक्ष की पूर्ण विजय की नहीं बल्कि ऐसे सामाजिक संवाद की है जिसमें परंपरा भी सम्मानित रहे और संविधान भी सर्वोच्च बना रहे। यही संतुलन भविष्य के भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अब जेनेरिक दवाओं संबंधी नई चिंताएं

भारत को अपनी निर्भरता केवल अमेरिकी बाजार तक सीमित न रखकर यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के उभरते बाजारों में अपना निर्यात तेजी से बढ़ाना चाहिए। पारंपरिक जेनेरिक दवाओं के स्थान पर अब जटिल जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के शोध व विकास पर अधिक ध्यान देना होगा क अगस्त से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में आयातित जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने संबंधी नीति लागू की गई है।

डा. जयंतीलाल भंडारी

इस नीति के तहत 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2028 तक, यानी शुरुआती दो वर्षों के लिए, आयातित जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, ताकि अमेरिकी बाजार में दवा आपूर्ति में तुरंत कोई बाधा न आए। इसके पश्चात, 1 अगस्त 2028 से 31 जुलाई 2029 तक एक वर्ष के लिए दवाओं के मूल्य पर सीधे 100 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया जाएगा। अंततः 1 अगस्त 2029 के बाद इस टैरिफ को बढ़ाकर 200 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ट्रंप द्वारा जेनेरिक दवाओं पर इस कड़े टैरिफ ढांचे को लागू करने का मुख्य उद्देश्य विदेशी दवा कंपनियों को अमेरिका के भीतर निर्माण इकाइयां (मैन्युफैक्चरिंग प्लांट) स्थापित करने के लिए बाध्य करना है। जो दवा निर्माता दी गई इस समयावधि के भीतर अपना उत्पादन घरेलू स्तर पर अमेरिका में स्थानांतरित नहीं करेंगे, उन पर 200 प्रतिशत का भारी आर्थिक दंडस्वरूप टैरिफ लागू होगा। चूंकि भारतीय दवा उद्योग अमेरिकी बाजार का एक मुख्य आपूर्तिकर्ता है, इसलिए भारत पर इसका गहरा प्रभाव पडना स्वाभाविक ह।

ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष 26 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसे 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया। ट्रंप के दवा टैरिफ के उस निर्णय का भारतीय फार्मा कंपनियों पर विशेष असर नहीं हुआ था। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली कुल दवाओं में पेटेंट या ब्रांडेड दवाओं का हिस्सा महज 5 प्रतिशत ही है। यह दवा टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं हुआ जो अमेरिका के भीतर ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। ट्रंप ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि किसी फार्मा कंपनी की रुचि अमेरिका में दवाओं के विनिर्माण में है या किसी कंपनी ने अमेरिका में अपना प्लांट लगाना शुरू कर दिया है, तो उसे टैरिफ से पूर्ण छूट मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों को अमेरिकी भूमि पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस फैसले का सबसे अधिक प्रभाव उन देशों पर पड़ा जिनकी फार्मा कंपनियां अमेरिका को बड़े पैमाने पर ब्रांडेड दवाओं का निर्यात करती हैं, जिनमें आयरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देश प्रमुख हैं। यहां ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं और जेनेरिक दवाओं के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। ब्रांडेड दवाएं, यह मूल दवाएं होती हैं जिनकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने लंबे शोध और अनुसंधान के बाद की होती है। इसे बनाने वाली कंपनी को एक तय अवधि (जो आमतौर पर 20 साल की होती है) के लिए एकाधिकार या पेटेंट अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दवा नहीं बना सकती। जेनेरिक दवाएं, वे दवाएं होती हैं जो ब्रांडेड दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद बाजार में आती हैं। इन्हें ब्रांडेड दवा के समान फॉर्मूले का उपयोग करके ही बनाया जाता है। चूंकि जेनेरिक दवाओं का कोई नया पेटेंट नहीं होता और यह पूर्व-मौजूद फॉर्मूले पर आधारित होती हैं, इसलिए कंपनियों को शोध पर भारी-भरकम खर्च नहीं करना पड़ता।

यही कारण है कि जेनेरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बेहद कम होती है। विशेष बात यह है कि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाएं निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 10 अरब डॉलर की दवाइयां भेजीं, जो भारत के कुल वैश्विक दवा निर्यात का करीब एक-तिहाई से अधिक है। निश्चित रूप से, ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं के बाद अब जेनेरिक दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में घरेलू दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का यह कदम 'अमेरिका फर्स्ट' और 'मेक इन अमेरिका' की नीति का ही एक हिस्सा है। ट्रंप का यह भी मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भर रहना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका ने यह अनुभव किया है कि यदि दवाइयों की वैश्विक सप्लाई चेन टूटती है, तो देश में दवाओं की भीषण किल्लत हो सकती है। ऐसे में ट्रंप ने यह कदम अमेरिका की पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया है। ट्रंप द्वारा जेनेरिक दवाओं पर तुरंत टैरिफ न लगाकर दो वर्ष की छूट देने के पीछे कुछ विशेष कारण भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में डॉक्टर मरीजों के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनमें से हर 10 में से करीब 4 दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित जेनेरिक दवाएं होती हैं। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 80 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं। यदि जेनेरिक दवाओं पर तुरंत 100 प्रतिशत या 200 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाता, तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें रातों-रात आसमान छूने लगतीं। इससे आम अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अत्यधिक महंगी हो जातीं, जो सीधे तौर पर ट्रंप सरकार के लिए घरेलू असंतोष का कारण बन सकता था। वास्तव में, सस्ती भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां के स्वास्थ्य तंत्र के लिए लागत-बचत का एक प्रमुख जरिया हैं। ज्ञातव्य है कि भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है और वर्तमान में भारत विश्व के 200 से अधिक देशों को दवाओं का निर्यात करता है। देश में 3000 से अधिक दवा कंपनियां और 10500 से अधिक सक्रिय निर्माण इकाइयां हैं। मात्रा के मामले में भारतीय दवा उद्योग विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि मूल्य के लिहाज से यह 14वें स्थान पर आता है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और विभिन्न देशों के साथ हो रहे मुक्त व्यापार समझौतों के बल पर भारतीय फार्मा क्षेत्र का कारोबार वर्तमान 55-60 अरब डॉलर के स्तर से छलांग लगाकर अगले कुछ वर्षों में 130 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। चूंकि भारत में दवा उत्पादन की लागत अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए भारत वैश्विक बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली दवाओं के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं और 60 प्रतिशत टीकों (वैक्सीन) का उत्पादन भारत में ही होता है। इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनिवार्य टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए 70 प्रतिशत टीकों की आपूर्ति भी भारतीय कंपनियों द्वारा ही की जाती है। अब जेनेरिक दवाओं पर अमेरिकी टैरिफ की इस नई चुनौती से निपटने के लिए भारत को कई रणनीतिक बिंदुओं पर तुरंत ध्यान केंद्रित करना होगा। अगस्त 2026 से जुलाई 2028 तक मिलने वाली शून्य प्रतिशत शुल्क की अवधि का उपयोग भारतीय कंपनियों और सरकार को दीर्घकालिक रणनीति बनाने में करना होगा। भारत को अपनी निर्भरता केवल अमेरिकी बाजार तक सीमित न रखकर यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के उभरते बाजारों में अपना निर्यात तेजी से बढ़ाना चाहिए। पारंपरिक जेनेरिक दवाओं के स्थान पर अब जटिल जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के शोध व विकास पर अधिक ध्यान देना होगा।

शिव मंदिर विवाद पर हिंदू संगठनों का चक्काजाम, आरोपी पर एनएसए की मांग

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के कुंवरपुर गांव स्थित शिव मंदिर में कथित अभद्रता के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को हिंदू संगठनों ने पोहरी चौराहे पर करीब आधे घंटे तक चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी सोनू जाटव को जिलाबदर करने तथा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की मांग उठाई इससे पहले सकल हिंदू समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने के बाद उन्होंने एसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और फिर पोहरी चौराहे पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिया चक्काजाम के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा सूचना मिलने पर एसडीओपी सचिन कुमार धुर्वे और कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर यातायात बहाल किया गया हिंदू संगठनों का आरोप है कि 5 अगस्त को कुंवरपुर के प्राचीन शिव मंदिर में आरोपी ने हिंदू देवी-देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत कीं। वहीं सिरसौद थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

फोन टैपिंग मामले में रावतपुरा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई की फोन टैपिंग को बताया अवैध सभी रिकॉर्डिंग नष्ट करने के आदेश एफआईआर और चार्जशीट बरकरार

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फोन टैपिंग मामले में रावतपुरा संस्थान के चेयरमैन एवं कथावाचक रावतपुरा सरकार (रवि शंकर जी महाराज) को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई फोन टैपिंग को पूरी तरह गैरकानूनी करार देते हुए उसे रद्द कर दिया साथ ही टैपिंग के माध्यम से प्राप्त सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग और संबंधित सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं हालांकि, अदालत ने सीबीआई की एफआईआर और दाखिल चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया अब जांच एजेंसी को फोन टैपिंग से प्राप्त किसी भी सामग्री का उपयोग किए बिना अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष सीबीआई अदालत में अपना पक्ष साबित करना होगा।

यह मामला 30 जून 2025 को सीबीआई द्वारा देशभर के 35 मेडिकल संस्थानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रिश्वत फर्जी मरीजों और कथित घोस्ट फैकल्टी के जरिए मेडिकल कॉलेजों को अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट दिलाई जाती थी इसी मामले में रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन होने के कारण रावतपुरा सरकार को भी आरोपी बनाया गया था सीबीआई ने 28 जून 2025 को उनके फोन की निगरानी का आदेश जारी किया था बाद में गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग ने हलफनामे में दावा किया कि यह अनुमति 1 जून से 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी थी इस आदेश को रावतपुरा सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार से कड़ा सवाल पूछा कि जब मूल फोन टैपिंग आदेश 28 जून को जारी हुआ तो उसे 1 जून से प्रभावी मानते हुए पूर्व तिथि (बैकडेट) से मंजूरी किस आधार पर दी गई अदालत ने इस प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि रिकॉर्ड में इसका कोई वैध कानूनी आधार दिखाई नहीं देता अदालत ने यह भी पाया कि फोन टैपिंग के आदेश में कहीं भी सार्वजनिक आपातस्थिति या जनसुरक्षा जैसे आवश्यक कानूनी आधारों का उल्लेख नहीं किया गया था। आदेश केवल औपचारिक रूप से जारी कर दिया गया जबकि कानून के तहत ऐसी कार्रवाई के लिए स्पष्ट और ठोस कारण दर्ज होना अनिवार्य है अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि फोन टैपिंग किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार पर सीधा हस्तक्षेप है इसलिए ऐसी कार्रवाई केवल निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए ही की जा सकती है खंडपीठ ने 28 जून 2025 के सीबीआई के फोन टैपिंग आदेश 4 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुष्टि आदेश तथा 15 सितंबर 2025 को रिव्यू कमेटी की कार्यवाही को निरस्त कर दिया साथ ही स्पष्ट किया कि रायपुर स्थित विशेष सीबीआई अदालत इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी लेकिन फोन टैपिंग से प्राप्त किसी भी रिकॉर्डिंग या उससे जुड़े साक्ष्य पर विचार नहीं करेगी मामले का फैसला केवल अन्य वैध दस्तावेजों परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी किसान अजमेर सिंह के लिए संकट की ढाल

प्राकृतिक आपदा से गेहूं की फसल खराब होने पर मिला 24 हजार का बीमा दावा, किसान ने योजना को बताया भरोसे का सहारा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कृषि पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है और मौसम की अनिश्चितता कई बार किसानों की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देती है ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच बनकर सामने आ रही है मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पसौरी निवासी किसान अजमेर सिंह की कहानी इस योजना की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है अजमेर सिंह ने अपनी लगभग 4 एकड़ कृषि भूमि में गेहूं की फसल बोई थी खेती के साथ-साथ उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा भी कराया फसल तैयार होने से पहले प्राकृतिक कारणों से उनकी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फसल खराब होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीमा दावा प्रस्तुत किया संबंधित अधिकारियों द्वारा दावे का सत्यापन किए जाने के उपरांत बीमा कंपनी ने उन्हें 24,000 की सहायता राशि स्वीकृत कर प्रदान की यह राशि उनके लिए आर्थिक संबल साबित हुई और खेती से जुड़े नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण सहायता मिली अजमेर सिंह बताते हैं कि यदि उन्होंने फसल का बीमा नहीं कराया होता तो नुकसान की भरपाई करना बेहद कठिन हो जाता उनका कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए कठिन परिस्थितियों में एक मजबूत सुरक्षा कवच का कार्य करती है योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों को दोबारा खेती करने का आत्मविश्वास देती है और उन्हें विपरीत परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है उन्होंने जिले के सभी किसानों से अपील की कि वे अपनी फसलों का समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि अथवा अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने पर उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके और आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े अजमेर सिंह ने किसानों के हित में संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के किसान हितैषी प्रयासों एवं कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज किसानों के लिए केवल बीमा योजना नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास का मजबूत आधार बनकर उभर रही है।

मनरेगा की लंबित मजदूरी राशि राज्य से जारी, श्रमिकों के खातों में अगले एक-दो सप्ताह में पहुंचेगी राशि

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है भारत सरकार द्वारा पूर्व से लंबित समस्त मजदूरी राशि राज्य शासन को जारी कर दी गई है इसके साथ ही श्रमिकों के बैंक खातों में राशि जमा करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा आगामी एक-दो सप्ताह के भीतर सभी रोजगार प्राप्त श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी की राशि जमा हो जाएगी मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए विभिन्न निर्माण एवं जनहितकारी कार्य संचालित किए जाते हैं इन कार्यों में लगे श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा लंबित मजदूरी राशि जारी किए जाने से भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई है और श्रमिकों को शीघ्र ही इसका लाभ मिलेगाइसके अतिरिक्त वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत भी राज्य शासन को अग्रिम रूप से पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है इसके फलस्वरूप फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) तैयार होने के उपरांत नियमानुसार तत्काल मजदूरी भुगतान किया जा रहा है इससे योजना के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो रहा है संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान अथवा योजना के अन्य मदों के भुगतान के लिए किसी प्रकार की वित्तीय समस्या नहीं है। आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने के कारण सभी स्वीकृत भुगतान निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार नियमित रूप से किए जा रहे हैं इसलिए श्रमिकों अथवा जनप्रतिनिधियों को किसी प्रकार की भ्रांति या आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है सभी जनप्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे इस संबंध में योजना से जुड़े श्रमिकों तथा आम नागरिकों को सही एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि मजदूरी भुगतान को लेकर किसी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रसार न हो तथा पात्र श्रमिकों तक शासन की यह महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पहुंचे।

10 अगस्त को होगी जिला पंचायत एमसीबी की सामान्य सभा की बैठक

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिला पंचायत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की सामान्य सभा की बैठक 10 अगस्त 2026 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी), अमृतधारा, लाई, जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह करेंगी बैठक में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जिले के सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सामान्य सभा में जिले के विकास कार्यों, ग्रामीण अधोसंरचना तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे बैठक के एजेंडा में 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों के अनुमोदन पर विचार-विमर्श प्रमुख रूप से शामिल रहेगा। इसके अलावा जिला पंचायत विकास निधि से प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों पर भी चर्चा कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जाएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों से निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर बैठक के एजेंडा के अनुरूप चर्चा एवं निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों से जिले में विकास कार्यों को गति मिलने तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई दिशा मिलने की अपेक्षा है।

बिहान योजना से बदली प्रमिला दीदी की जिंदगी, किराना व्यवसाय ने दिलाई आत्मनिर्भरता की नई पहचान

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। आर्थिक तंगी से जूझ रही मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम केवटी की प्रमिला दीदी ने बिहान-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं प्रमिला दीदी वर्ष 2017 में गठित जय माता दी महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह के माध्यम से उन्होंने नियमित बचत, वित्तीय प्रबंधन और स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किए अपनी सक्रियता और जिम्मेदारी के चलते वे समूह में पुस्तक संचालक रहीं तथा बाद में एफएलसीआरपी कैडर के रूप में भी कार्य करने लगीं समूह को मिले रिवॉल्विंग फंड से उन्होंने सबसे पहले दो हजार रुपये का ऋण लेकर कृषि कार्य शुरू किया इससे आत्मविश्वास बढ़ा तो बाद में सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) से दस हजार रुपये का ऋण लेकर गांव में छोटी किराना दुकान शुरू की। सीमित पूंजी से शुरू हुआ यह कारोबार आज ग्रामीणों की जरूरतों का भरोसेमंद केंद्र बन चुका है वर्तमान में प्रमिला दीदी को किराना दुकान से प्रतिदिन लगभग 200 रुपये का लाभ और करीब छह हजार रुपये मासिक आय प्राप्त होती है वहीं एफएलसीआरपी कैडर के रूप में कार्य करने से उन्हें लगभग पांच हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त आय होती है। इस तरह उनकी कुल मासिक आय लगभग 11 हजार रुपये तक पहुंच गई है अब उन्हें घरेलू जरूरतों के लिए किसी साहूकार से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रमिला दीदी का कहना है कि समूह से मिले प्रशिक्षण वित्तीय सहयोग और निरंतर मार्गदर्शन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी उनकी सफलता से प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

स्मार्ट मीटर से बदला बिजली उपभोक्ताओं का अनुभव, मनेन्द्रगढ़ के अंकुर जैन बोले- सही बिलिंग से बढ़ा भरोसा

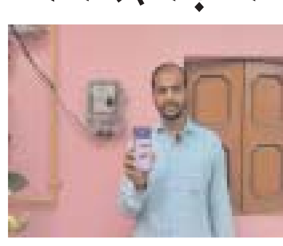

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी विश्वसनीय और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटर प्रभावी साबित हो रहे हैं आधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ऊर्जा प्रबंधन को भी आसान बना रही है मनेन्द्रगढ़ निवासी अंकुर जैन ने स्मार्ट मीटर के उपयोग से मिले सकारात्मक अनुभव साझा करते हुए इसे बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी पहल बताया अंकुर जैन ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी बिजली खपत को लेकर जागरूकता बढ़ी है पहले मासिक बिल आने के बाद ही बिजली उपयोग का अनुमान लग पाता था लेकिन अब डिजिटल माध्यम से समय-समय पर खपत की जानकारी उपलब्ध हो जाती है इससे यह समझना आसान हो गया है कि किस समय और किन उपकरणों के कारण बिजली की अधिक खपत हो रही है जिससे अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण संभव हो पाया है उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था है अब जितनी बिजली की खपत होती है उसी के अनुरूप बिल प्राप्त होता है इससे बिल संबंधी भ्रम की स्थिति काफी हद तक समाप्त हुई है और उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ा है सटीक जानकारी मिलने से घरेलू बिजली उपयोग की बेहतर योजना बनाना भी आसान हो गया है अंकुर जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) की डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से बिजली बिल खपत और अन्य आवश्यक जानकारियां ऑनलाइन आसानी से देखी जा सकती हैं अब उपभोक्ताओं को केवल बिल आने का इंतजार नहीं करना पड़ता बल्कि वे अपनी बिजली खपत पर लगातार नजर रखते हुए जरूरत के अनुसार उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं उन्होंने स्मार्ट मीटर को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी पहल बताते हुए कहा कि जब उपभोक्ता अपनी दैनिक बिजली खपत को समझने लगते हैं तो अनावश्यक बिजली उपयोग स्वतः कम होने लगता है इससे बिजली की बचत के साथ घरेलू बजट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उनका मानना है कि स्मार्ट मीटर भविष्य की आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बिजली व्यवस्था का मजबूत आधार बनेंगे तथा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

खड़गवां में स्वच्छता का जमीनी जायजा, राज्य सलाहकार ने प्लास्टिक प्रबंधन और अपशिष्ट पृथक्करण पर कसा फोकस

ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई जल्द शुरू करने के निर्देश, जोश अभियान की सराहना एफएसटीपी स्थापना की प्रक्रिया तेज करने पर जोर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य सलाहकार पुरुषोत्तम पांडा ने गुरुवार को विकासखंड खड़गवां की ग्राम पंचायत पौड़ीडीह, खड़गवां एवं लालपुर का भ्रमण कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) नियम-2026 के तहत संचालित गतिविधियों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा जनजागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए ग्रामीणों से सीधे संवाद किया भ्रमण के दौरान राज्य सलाहकार ने ग्राम पंचायत पौड़ीडीह

में ग्रामीणों को सोर्स सेग्रीगेशन (स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण) का महत्व समझाया डस्टबिन का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बताया कि गीले सूखे घरेलू खतरनाक एवं अन्य प्रकार के कचरे का अलग-अलग संग्रहण स्वच्छ एवं स्वस्थ गांव की मजबूत आधारशिला है उन्होंने कहा कि यदि घर से ही कचरे का सही तरीके से पृथक्करण किया जाए तो अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदलना अधिक आसान हो जाता है उन्होंने ग्रामीणों से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल (3आर) की अवधारणा को अपनाने की अपील करते हुए प्लास्टिक के उपयोग में कमी उसके पुनः उपयोग एवं वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण के विभिन्न उपायों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रभावी

प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का भी सशक्त माध्यम बन सकता है निरीक्षण के दौरान राज्य सलाहकार ने ग्राम पंचायत पौड़ीडीह में स्थापित प्लास्टिक प्रबंधन इकाई को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके संचालन से गांव में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित होगा तथा स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित व्यवसायिक मॉडल विकसित कर ग्रामीणों की आय बढ़ाई जा सकेगी राज्य सलाहकार ने जिले के नवाचार जोश - जर्नी ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन' अभियान की सराहना करते हुए स्वच्छता प्रहरी राजेश द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस अभिनव पहल से विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा मिला है, विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार हुआ है स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ी है तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्रस्तावित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) की स्थापना पर भी विस्तृत चर्चा हुई राज्य सलाहकार ने स्थल चयन एवं आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संयंत्र की स्थापना से मलीय कीचड़ का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित होगा और जिले में ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों के निर्माण को नई गति मिलेगी।

शादी के एक महीने बाद युवक ने फांसी लगाई :पत्नी पांच दिन से मायके में थी सुसाइड नोट नहीं मिला

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे की महुअर कॉलोनी में 25 वर्षीय एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली युवक की शादी जुलाई माह में महज एक माह पहले हुई थी घटना के समय उसकी पत्नी पिछले पांच दिनों से अपने मायके में थी सूचना मिलने पर करेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महुअर कॉलोनी निवासी विवेक झा (25) ने गुरुवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की घटना की सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ पुलिस का कहना है कि विवेक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जांच की जा रही है। करेरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

खंडवा में शेयर मुनाफे का झांसा, 21 लाख ठगे

● पुलिस ने राजस्थान से तीन साइबर आरोपियों को पकड़ा, 2.55 लाख नकद जत

मीडिया ऑडीटर,खंडवा (निप्र)। शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 21 लाख 63 हजार 970 रुपए की साइबर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को खंडवा कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के टोंक जिले से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 55 हजार 200 रुपए नकद बरामद किए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।

'बादशाह ब्रोकर' के नाम पर लगाया लाखों का चूना: कोतवाली पुलिस के अनुसार, 8 मई 2025 को एक फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 'बादशाह ब्रोकर' नाम से संचालित एक कंपनी ने शेयर मार्केट में निवेश पर अधिक मुनाफा दिलाने का लालच दिया। आरोपियों ने विभिन्न ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए फरियादी से 21 लाख 63 हजार 970 रुपए अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। जब न तो कोई लाभ मिला और न ही आरोपियों से संपर्क हो पाया, तब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

तकनीकी जांच से राजस्थान तक पहुंची पुलिस: मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने साइबर ट्रैकिंग, बैंक खातों के लेनदेन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तीन आरोपी गिरफ्तार, नकदी बरामद

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक कुशवाह (26), विवेक खींची (30) और आत्माराम मेहरा (28), निवासी उनियारा, जिला टोंक (राजस्थान) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख 55 हजार 200 रुपए नकद बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

पूरे साइबर नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किसी संगठित साइबर गिरोह का हिस्सा हैं या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर अन्य लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया है या नहीं। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल फोन, डिजिटल लेनदेन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी गहन जांच कर रही है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रवीण आर्य, इंस्पेक्टर हंस झींझोरे, पंकज सिंह सोलंकी, शिवम ओझा, रूपेश बामने और साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचकर कार्रवाई को सफल बनाया।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

खंडवा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शेयर मार्केट या ऑनलाइन निवेश के नाम पर मिलने वाले किसी भी अनजान कॉल, लिंक, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया विज्ञापन पर बिना जांच भरोसा न करें।

मानसून की रफ्तार थमी, अगले 2-3 दिन झमाझम बारिश

मीडिया ऑडीटर,रायसेन (निप्र)।जिले में मानसून की रफ्तार थमी हुई है। अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को अभी राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो से तीन दिन जिले में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गरज-चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। व्यापक बारिश की संभावना नहीं है। तेज बारिश के संकेत भी नहीं हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान सीमा पर बने चक्रवाती परिसंचरण से क्षेत्र में नमी बनी हुई है। मानसून ट्रफ उत्तर भारत की ओर सक्रिय है। इस वजह से मध्य प्रदेश के इस हिस्से में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रहा है। ट्रफ के दक्षिण की ओर खिसकने तक जिले में खंड-बारिश होगी। स्थानीय बौछारों का दौर जारी रह सकता है। बढ़ने लगा दिन-रात का तापमान : बारिश की कमी का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जिले में 1 जून से 5 अगस्त तक औसतन 447.41 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। सबसे अधिक बारिश गैरतगंज (570 मिमी), बेगमगंज (542.5 मिमी) और उदयपुरा (529 मिमी) में हुई, जबकि सिलवानी (361.6 मिमी) और रायसेन (370 मिमी) में अपेक्षाकृत कम वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में जिले में औसतन सिर्फ 0.47 मिलीमीटर बारिश हुई।

सागर में कुल्हाड़ी से हमला कर की थी लूट, 3 महीने से फरार हत्या के प्रयास के दो आरोपी सागर में गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर,सागर (निप्र)। सागर के सुरखी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास और लूट के मामले में तीन महीने से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, लूटा गया मोबाइल, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की पायल बरामद की है। दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। शराब पीने के लिए मांगे थे पैसे पुलिस के अनुसार, घटना 6 मई की रात करीब 8 बजे की है। फरियादी अपने टपरे पर मौजूद था, तभी मुलायम लोधी, गुड्डी खान और उनका एक साथी वहां पहुंचे। तीनों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी ने रुपये देने से इनकार किया तो विवाद बढ़ गया।

कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ वार: गुस्साए आरोपियों ने फरियादी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोप है कि मुख्य आरोपी मुलायम लोधी ने सिर, पीठ और हाथ की उंगलियों पर लगातार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ आए दूसरे आरोपी ने लात-घूंसों और डंडों से भी मारपीट की।

बीच-बचाव करने आई महिला पर भी हमला: मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची टीना पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपी गुड्डी खान ने कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे टीना के सिर में चोट आई। वारदात के बाद आरोपी फरियादी का मोबाइल फोन, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की पायल लूटकर फरार हो गए।

5-5 हजार का इनाम था घोषित: घटना के बाद सुरखी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास और लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। लगातार दबिश और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था।

सागर में राजा बाबा जंगल में पुलिस पर पथराव

गाड़ी में भी की थी तोड़फोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगपुर गंजन स्थित राजा बाबा जंगल में पुलिस टीम पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के दौरान पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था और एक प्रधान आरक्षक घायल हो गया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। मामले के तीन अन्य आरोपी अब भी फरार हैं।

अफवाह के बाद जंगल में जुटी थी हजारों लोगों की भीड़: पुलिस के अनुसार, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के राजा बाबा जंगल में कीमती पत्थर और आभूषण मिलने की अफवाह फैल गई थी। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग जंगल में खुदाई करने पहुंच गए। भीड़ बढ़ने की सूचना वन विभाग ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

भीड़ हटाने पहुंची पुलिस पर हुआ पथराव: पुलिस जब लोगों को जंगल से हटाने और स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया।

पथराव में पुलिस वाहन के शीशे टूट गए, जबकि एक प्रधान आरक्षक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बलवा और शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज: घटना के बाद देवरी थाना पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं।

जंगल और आसपास के इलाकों में दी गई दबिश: जांच के दौरान पुलिस ने जंगल और आसपास के गांवों में लगातार दबिश दी। बुधवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डब्बू ग्वालिया और गुड्डू ग्वालिया को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई।

तीन आरोपी अब भी फरार: पुलिस के अनुसार, इस मामले में नामजद आरोपी शब्बीर ग्वालिया, कल्लू और अन्नू ग्वालिया अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

न्यायालय ने भेजा जेल: देवरी थाना प्रभारी हरिराम मानकर ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

नर्मदापुरम में आधे घंटे झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत, इस सीजन अब तक 16 इंच वर्षा

मीडिया ऑडीटर,नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे तेज बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से शहर तरबतर हो गया। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश रुकने के बाद मौसम साफ हो गया। नर्मदापुरम के साथ इटारसी में भी अच्छी बारिश हुई। बुधवार सुबह से मौसम साफ था। दोपहर करीब 2:50 बजे अचानक काले बादल छा गए। इसके बाद तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में तेज बारिश में बदल गई। दिनभर की तेज धूप और उमस के बाद बारिश से मौसम सुहावना हो गया।

4 से 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया कि जिले और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बहुत अधिक बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

अब तक औसतन 16 इंच बारिश: मानसून सीजन में अब तक जिले में औसतन 16 इंच बारिश दर्ज की गई है।

रायसेन कोर्ट परिसर में रक्तदान महादान का संदेश

वकील और पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों ने किया रक्तदान,जरूरतमंद मरीजों के लिए जुटाईं 40 यूनिट रक्त

मीडिया ऑडीटर,रायसेन (निप्र)। रायसेन के बेगमगंज न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ की पहल पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और समाजसेवियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 40 यूनिट रक्त एकत्र कर जरूरतमंद मरीजों के लिए मानव सेवा का संदेश दिया गया।

रक्तदान को जनआंदोलन बनाने की पहल: सुबह 11 बजे शुरू हुए शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना था, ताकि जरूरत के समय मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। आयोजकों ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा अभियान बताया।

न्यायाधीश ने किया पहला रक्तदान: शिविर में जिला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सविता ओगले, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी, व्यवहार न्यायाधीश अन्ना ग्लोरी महेश्वरी और श्वेता चौहान मौजूद रहीं।

कार्यक्रम की शुरुआत न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने रक्तदान कर की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी की जान बचाई जा सकती है।

अधिवक्ता संघ ने बताया उद्देश्य: अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष प्रभाकर बुंदेला ने बताया यह रक्तदान शिविर जरूरतमंद मरीजों को समर्पित था। उनका कहना था कि समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को बढ़ावा देना और लोगों को इस अभियान से जोड़ना ही आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।

सभी वर्गों की रही भागीदारी: शिविर में अधिवक्ताओं के अलावा न्यायालय कर्मचारी, पुलिसकर्मी, मुंशी और समाजसेवियों ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आयोजन के दौरान लोगों ने रक्तदान को सामाजिक दायित्व बताते हुए भविष्य में भी ऐसे अभियानों में भाग लेने का संकल्प लिया।

बुधनी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, ड्राइवर हिरासत में लिया गया, वाहन जब्त

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 314 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं, बुधनी में हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने स्वयं सैकड़ाखेड़ी जोड़ पहुंचकर कार्रवाई का जायजा लिया और पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए। इन कार्रवाइयों से 1,57,000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। एक ओर जहां पुलिस यह अभियान चला रही थी, वहीं बुधनी में एक सड़क हादसा हो गया। रात लगभग 8:30 बजे एनएच-46 पर भारत पेट्रोलियम पंप के सामने एक आयशर ट्रक (RJ 11 GD 5158) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए कमलेश यादव की मोटरसाइकिल (MP 05 ZJ 7102) को टक्कर मार दी। इस टक्कर में कमलेश यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बुधनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

छतरपुर में 37 पेटी अवैध शराब जब्त

पुलिस सायरन सुन तस्कर ब्रेजा कार छोड़कर भागे, 9 लाख का माल बरामद

मीडिया ऑडीटर,छतरपुर (निप्र)। छतरपुर सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुधवार तड़के अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 37 पेटी देशी शराब और एक विटारा ब्रेजा कार जब्त की है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके से कार छोड़कर फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई नई तहसील फोरलेन ब्रिज के पास की गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो सायरन की आवाज सुनकर तस्कर भाग निकले। जांच के दौरान कार से 37 पेटी देशी शराब बरामद हुई।

जब्त शराब की कुल मात्रा 333 लीटर बताई गई है। पुलिस ने शराब और कार सहित करीब 9 लाख रुपए का सामान जब्त किया है।

आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज: मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब जब्त कार के नंबर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय ने बताया कि वाहन नंबर के आधार पर कार मालिक और आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस कंट्रोल और हाईवे पर लगे कैमरों सहित अन्य सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले और नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष श्रोत्रिय, उपनिरीक्षक खीस्तोफर टोप्पो सहित पुलिस टीम शामिल रही।

औबेदुल्लागंज-बैतूल नेशनल हाइवे पर ट्रक ने युवक को कुचला, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, आधे घंटे बंद रहा फोरलेन

मीडिया ऑडीटर,नर्मदापुरम (निप्र)। औबेदुल्लागंज-बैतूल नेशनल हाईवे फोरलेन पर बुधनी बायपास के पास बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बगवाड़ा निवासी कमलेश यादव के रूप में हुई है।

हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और निर्माण एजेंसी की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बुधनी बायपास फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया।

सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आया व्यक्ति: जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 10:30 बजे कमलेश यादव बुधनी फोरलेन पर सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए।

निर्माण एजेंसी की लापरवाही का लगाया आरोप: हादसे से नाराज ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बुधनी बायपास पर सर्विस रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं। उनका कहना था कि निर्माण स्थल पर न तो उचित संकेतक लगाए गए हैं और न ही सुरक्षित डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। इसी लापरवाही के कारण इस क्षेत्र में लगातार हादसों का खतरा बना हुआ है।

आधे घंटे तक लगा रहा चक्काजाम: आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधनी बायपास फोरलेन पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें समझाया, जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद जाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका।

गुरुवार को हुआ पोस्टमार्टम: जाम खुलवाने के बाद बुधनी पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए बुधनी अस्पताल भिजवाया। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क पार करने के दौरान ट्रक की चपेट में आने से कमलेश यादव की मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को शांत कराया गया।

हॉकी इंडिया ने किया जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान

नई दिल्ली एजेंसी। शिलेइमा चानू बनीं कप्तान हॉकी इंडिया ने गुरुवार को एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान किया। यह टीम 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएगी। इस टीम में 18 खिलाड़ियों के साथ दो वैकल्पिक खिलाड़ी को भी टीम में जगह दी गई है। टीम की अगुवाई मिडफील्डर खाइदेम शिलेइमा चानू करेंगी। चानू ने नए कोच टिम व्हाइट की देखरेख में काफी तैयारी की है। वह इससे पहले, साल की शुरुआत में भी टीम की कमान संभाल चुकी हैं। महाद्वीपीय टूर्नामेंट की तैयारियों के तहत हाल ही में टीम यूनाइटेड किंगडम (यूके) के एक अच्छे एक्सपोजर टूर से लौटी है। इस टूर से खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैचों का कीमती अनुभव और जरूरी बातें सीखने को मिलीं, जिससे जूनियर एशिया कप से पहले उनकी तैयारियां और मजबूत हुई हैं। यह टूर्नामेंट कॉन्टिनेंट की टॉप जूनियर टीमों को एक साथ लाएगा, जो एशियाई हॉकी टैलेंट की अगली पीढ़ी के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म का काम करेगा। मैच शेड्यूल और पूल के संयोजन की घोषणा टूर्नामेंट शुरू होने के करीब की जाएगी। कोच टिम व्हाइट ने कहा, 'मुझे इन युवा खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और पक्के इरादे पर गर्व है, जिन्होंने जूनियर एशिया कप के लिए टीम में अपनी जगह बनाई है।पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने अपने खेल के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और मैंने उन्हें अकेले और एक टीम के तौर पर आगे बढ़ते देखा है। '

व्हाइट ने खिलाड़ियों से इस मौके का पूरा फायदा उठाने और इसे अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक लॉन्चपैड के तौर पर देखने को कहा।

उन्होंने कहा, 'यह टूर्नामेंट एशिया के बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने और बड़े लक्ष्यों की ओर अपना सफर जारी रखने का एक अहम मौका है। हम हर मैच में आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ उतरेंगे। मुझे यकीन है कि इस ग्रुप में देश को गर्व महसूस कराने का टैलेंट और कैरेक्टर है। '

● **जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम :**
गोलकीपर : निधि, एंगिल हर्षा रानी मिंज
डिफेंडर : पूजा साहू, सुप्रिया, पूजा मलिक, पार्वती टोपनो, मधु
मिडफील्डर : खाइदेम शिलेमा चानू (कप्तान), तनुजा टोप्पो, बिनिमा धन, रोशनी आइंद, गीता यादव
फॉरवर्ड : लालरिनपुई, पूर्णिमा यादव, सुखवीर कौर, कृष्णा शर्मा, सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिदार
वैकल्पिक खिलाड़ी : एफ लालबियाक्सियामी, तनुश्री दिनेश कडू।

पिछले 10 महीने ने मेरी ऐसी परीक्षा ली

नई दिल्ली एजेंसी। फिटनेस से जुड़ी परेशानियों से करीब एक साल तक जूझने के बाद भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि पिछले 10 महीने उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे और उन्होंने ऐसे दौर का सामना किया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता 28 साल के इस खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर अपने पदकों के संग्रह में एक और उपलब्धि जोड़ी। वह मुख्य रूप से जांघ की मांसपेशियों की चोट और कुछ अन्य शारीरिक परेशानियों से प्रभावित रहे थे। चोट के कारण नीरज का सत्र देर से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने ग्लास्गो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 85.83 मीटर के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ अपनी लय हासिल कर ली। नीरज ने इंस्टाग्राम पर राष्ट्रमंडल खेलों के प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'कुछ भाले लंबी दूरी तय करते हैं और कुछ पल पूरी यात्रा का भार अपने साथ लेकर आते हैं। पिछले 10 महीने ने मेरी ऐसी परीक्षा ली, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी।' उन्होंने कहा, 'कई चोटों से उबरना, अपने शरीर को दोबारा मजबूत बनाना, फिर से लय हासिल करना और उस समय धैर्य रखना जब मैं केवल प्रतियोगिता में उतरना चाहता था। मैं हर दिन अभ्यास कर रहा था, लेकिन यह भी नहीं पता था कि इस साल मुझे खेलने का मौका मिलेगा या नहीं।' नीरज ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन चोट के कारण 2022 के सत्र में हिस्सा नहीं ले सके थे। पिछले साल सितंबर में विश्व चैंपियनशिप से ठीक पहले उन्हें कमर के निचले हिस्से में चोट लगी थी और राष्ट्रमंडल खेलों से पहले उन्होंने केवल एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में खराब मौसम के कारण मुश्किल परिस्थितियों के बीच नीरज को श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराजे 89.75 मीटर के थ्रो के साथ पीछे छोड़ा।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड दमदार

2015 में मिली थी आखिरी हार

नई दिल्ली एजेंसी। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 13 अगस्त से होने जा रहा है। सीरीज में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम बुधवार को श्रीलंका पहुंच चुकी है। मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड दमदार रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें से 22 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, जबकि 7 मैचों में श्रीलंका ने बाजी मारी है। 17 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। खास बात यह है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले आखिरी 10 टेस्ट मैचों में एक बार भी हार का सामना नहीं किया है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में आखिरी हार साल 2015 में मिली थी यानी पिछले 11 साल से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अजेय रही है। भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले ही बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी इंजरी से न उबर पाने के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के युवा गेंदबाज आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है।

आकिब ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान खींचा है। वह जम्मू-कश्मीर की ओर से भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्वॉडः

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी।

वहीं, साई सुदर्शन की फिटनेस पर भी अभी सवाल है, हालांकि 'क्रिकबज' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुदर्शन पहले टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे और वह 8 अगस्त तक टीम से जुड़ सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच 13 अगस्त से गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

इसके बाद सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी कोलंबो का सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान करेगा, जिसका आगाज 23 अगस्त से होना है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने दमदार रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी।

कोहली अपने रन-चेज का राज शेयर नहीं करते थे

संन्यास के बाद रहाणे ने किया खुलासा

लंदन एजेंसी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने पूर्व टेस्ट कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के साथ अपनी बैटिंग पार्टनरशिप को याद किया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अच्छे तालमेल और मेरे नैचुरल गेम के लिए विराट के प्रोत्साहन ने उन्हें लंबे फॉर्मेट में सफल होने में मदद की। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्टार बल्लेबाज व्हाइट-बॉल क्रिकेट में शानदार तरीके से रन चेज करने के पीछे के राज और कैलकुलेशन को अपने टीम के साथियों के साथ भी शेयर नहीं करते थे।

अजिंक्य ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट पर यह बात कही। इस पॉडकास्ट को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन, सर एलिस्टर कुक, फिल टफनेल और डेविड 'बंबल' लॉयड होस्ट करते हैं। पॉडकास्ट के दौरान भारतीय मिडिल-ऑर्डर के अहम खिलाड़ी ने कहा कि विराट व्हाइट-बॉल क्रिकेट में शानदार रन-चेज के पीछे के राज और कैलकुलेशन का खुलासा नहीं करते थे।

उन्होंने कहा, 'यह उनका दिमाग और उनके दिमाग में चल रही कैलकुलेशन है। लेकिन यह उनका राज है। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। वह आपको कोई सुराग नहीं देंगे। सही समय पर सोच-समझकर रिस्क लेने की उनकी काबिलियत ही अहम है। रू- धोनी भी ऐसे ही थे। लेकिन विराट के दिमाग में चलने वाली कैलकुलेशन कुछ अलग ही होती थी।'

बल्लेबाज़ ने कहा कि वह और विराट एक-दूसरे के पूरक थे क्योंकि उनके स्वभाव अलग-अलग थे, विराट आक्रामक थे और अजिंक्य शांत रहते थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विराट के साथ बनी पार्टनरशिप के बारे में बात की और बताया कि कैसे 37 साल के विराट गेंदबाजों का आक्रामक तरीके से सामना करते थे। उन्होंने यह भी याद किया कि विराट को गेंदबाजों का सामना करने में कितना मजा आता था और कैसे वह अपने साथी 'अज्जू' को अपना नैचुरल अटैकिंग गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे।

रहाणे ने कहा, 'उनके आक्रामक स्वभाव और मेरे शांत स्वभाव के कारण हम एक-दूसरे के बहुत अच्छे पूरक थे। हमारी सफल पार्टनरशिप के पीछे पॉजिटिव और खुलकर बातचीत करना था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी कई अच्छी पार्टनरशिप रहीं। उनमें, जब भी विराट किसी खास गेंदबाज के खिलाफ जाने के बारे में सोचते थे और मेरा जवाब पॉजिटिव होता था, तो वह उसे और बेहतर तरीके से करते थे।'

उन्होंने कहा, 'विराट को हमेशा यह पसंद था कि लोग उन्हें चुनौती दें। और वह मुझसे पूछते थे कि क्या उन्हें विरोधी खिलाड़ी को स्लेज करना चाहिए। मैं उनसे कहता था, 'हां, जरूर करो' क्योंकि यही उनके लिए काम करता था। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, और हम मैदान के बाहर भी एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे। हम क्रिकेट के बारे में बहुत बातें करते थे, जो आजकल देखने को नहीं मिलता। वह हमेशा सकारात्मक रहते थे और मुझसे कहते थे कि किसी गेंदबाज पर हमला करने में कभी न हिचकिचाएं। वह हमेशा सकारात्मक रहते थे।'

उन्होंने कहा, 'बस अपना खेल खेलो'। मेरे लिए, स्वाभाविक रूप से मैं... मैं एक आक्रामक क्रिकेटर, आक्रामक बल्लेबाज हूं। इसलिए उन्होंने कहा, 'अगर आपको किसी खास गेंदबाज पर हमला करने का मन करे, तो बिल्कुल भी न हिचकिचाएं'। तो वह हमेशा सकारात्मक रहते थे। उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि 'ठीक है, देखते हैं कैसा लगता है, या 10-15 गेंदें खेल लो और फिर अपना खेल खेलो'। 'अगर पहली गेंद पर ही हमला करने का मन करे, तो जरूर करो।

मार्श और रूट SA20 में शामिल होने वाले बड़े नामों में शामिल

JSK ने प्लेसिस को किया रिलीज

केपटाउन एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख लीग ᵴ20 की छह फ्रेंचाइजी ने सीजन 5 के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों और प्री-ऑक्शन साइनिंग की पुष्टि कर दी है। इसके बाद विदेशी खिलाड़ियों की एक शानदार लिस्ट सामने आई है, जिसमें मिशेल मार्श, सैम करन, जो रूट, फिल साल्ट और जेसन होल्डर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। खिलाड़ियों की नीलामी होनी अभी शेष है। डरबन सुपर जायंट्स और पार्ल रॉयल्स ने पहले ही अपनी 19 खिलाड़ियों की टीम पूरी कर ली है, जबकि बाकी चार फ्रेंचाइजी में अभी भी 19 जगहें खाली हैं। ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मार्श तीन बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप से जुड़कर अपना पहला ᵴ20 सीजन खेलने के लिए तैयार हैं। मार्श, जो 'द हंड्रेड' में सनराइजर्स फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, टीम की पहले से ही मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप को और ताकत देंगे। इस लाइन-अप में क्विंटन डी कॉक, मैथ्यू ब्रीट्जके, जॉर्डन हरमन और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। डरबन सुपर जायंट्स ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को अपनी टीम में शामिल किया है। करन पहले दो सीजन में एमआई केप टाउन के साथ खेलने के बाद लीग में वापसी कर रहे हैं। सुपर जायंट्स में करन अपने साथी खिलाड़ी जोस बटलर के साथ जुड़ेंगे।

जोस बटलर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने

कहा- यह भारतीय तोड़ सकता है रिकॉर्ड

मैनचेस्टर एजेंसी। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर, जिन्होंने बुधवार को वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़कर टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का मुकाम हासिल किया, ने युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का समर्थन करते हुए कहा कि वे एक दिन यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

बटलर 'मेन्स हंड्रेड' टूर्नामेंट में अपनी टीम मैनचेस्टर सुपर जायंट्स (MSG) और वेल्श फायर के बीच हुए मैच के दौरान टी20 क्रिकेट में शीर्ष पर पहुंचे। उन्होंने 20 गेंदों में 250.00 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 51 रन बनाए जिसमें दो चौके और छह छक्के शामिल थे। बटलर ने 522 टी20 मैचों में अब तक 14,833 रन बनाए हैं जिसमें 9 शतक और 105 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने पोलार्ड (746 मैचों में 14,803 रन, दो शतक) और लंबे समय तक रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल (463 मैचों में 14,562 रन, 22 शतक और 88 अर्धशतक) को पीछे छोड़ दिया है। बटलर ने रिकॉर्ड बनाने के बाद स्काई स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकइन्फो ने बताया कि उन्हें टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बनने पर गर्व है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह रिकॉर्ड कभी न कभी टूटेगा और इसे तोड़ने वाले संभावित खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हो सकते हैं। बटलर ने कहा, 'यह वाकई बहुत अच्छा लगता है कि आपके नाम टी20 में सबसे ज्यादा रन हैं। कोई न कोई इसे एक दिन तोड़ेगा ही और शायद उसका नाम [वैभव] सूर्यवंशी हो, लेकिन यह गर्व का पल है।' सिर्फ 15 साल की उम्र में सूर्यवंशी ने T20I क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों में 151 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अपना पहला अवॉर्ड जीता, जबकि भारत ने सीरीज 3-0 से जीती। उनकी यह सफलता इस साल की शुरुआत में ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिली, जहां उन्होंने 439 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए जिससे उनकी जबरदस्त क्षमता का पता चलता है। बटलर ने कहा कि जब पोलार्ड हेड कोच के तौर पर MI लंदन के साथ हों, तो उनके खिलाफ खेलते हुए उनसे आगे निकलना उन्हें अच्छा लगता। साथ ही उन्होंने टी20 के महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल होने पर गर्व भी जताया।

10 बार के WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने पेशेवर रेस्लिंग से लिया संन्यास

वॉशिंगटनएजेंसी। कॉम्बैट स्पोर्ट्स के दिग्गज और 10 बार के WWE चैंपियन अमेरिकी रेसलर ब्रॉक लेसनर ने पेशेवर कुश्ती से संन्यास ले लिया है। 49 वर्षीय लेसनर ने मंगलवार को 'द पैट मैकफी शो' में कहा कि शनिवार को WWE समरस्लैम में उनकी उपस्थिति उनके करियर की आखिरी उपस्थिति होगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस साल की

शुरुआत में रेसलमेनिया में जब उन्होंने रिंग में अपने जूते और दस्ताने उतारे थे, तब उन्हें लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन अंतत: उन्होंने पिछले सप्ताहांत मिनियापोलिस में एक आखिरी हेल इन ए सेल मैच खेलने का विकल्प चुना। लेस्नर ने कहा, 'मैं आज दुनिया को यह बताने आया हूं कि मैंने संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा कि शनिवार मेरे लिए बहुत भावुक दिन था। यह थोड़ा अजीब था।

दीक्षा डागर लंदन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी

लंदन एजेंसी। दीक्षा डागर 2 मिलियन डॉलर की लंदन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। हर्टफोर्डशायर के सेंचुरियन क्लब में 6-9 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के साथ लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) का यूनाइटेड किंगडम लेग अपने आखिरी हफ्ते में प्रवेश कर रहा है। दीक्षा के साथ 120 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनमें अदिति अशोक, प्रणवी उर्स और रूकी (नए खिलाड़ी) अवनि प्रशांत भी शामिल हैं। चारों खिलाड़ी एलईटी सीजन के आखिरी दौर में अपनी लय बनाए रखने की कोशिश करेंगी। दीक्षा दो बार एलईटी खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वह 2026 में टूर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक रही हैं। पिछले हफ्ते एआईजी विमेंस ओपन में कट से बाहर होने के बावजूद, दीक्षा 'एलईटी रेस टू कोस्टा डेल सोल' स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर हैं। वह फिलहाल सबसे ऊंची रैंकिंग वाली भारतीय हैं। दीक्षा अपने तीसरे एलईटी खिताब की तलाश में हैं। साल 2023 में टॉप-3 में रहने वालीं दीक्षा 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' पर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को और बेहतर बनाना चाहती हैं। पांच बार की एलईटी चैंपियन अदिति अशोक जानी-पहचानी जगह पर वापसी कर रही हैं। हालांकि, इस सीजन में वह अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नजर नहीं आ सकी हैं, लेकिन भारतीय स्टार उस निरंतरता को फिर से हासिल करने की उम्मीद करेंगी जिसने उन्हें टूर की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बनाया है। वहीं, प्रणवी उर्स का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है और वह 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' में टॉप-50 में शामिल हैं, जबकि रूकी अवनि प्रशांत ने अपने पहले एलईटी सीजन में सभी को प्रभावित किया है, जो टॉप-50 में बनी हुई हैं।

यश ढुल ने सिर्फ 47 गेंदों पर ठोका जबरदस्त शतक

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली 6 को हराया

नई दिल्ली एजेंसी। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश से प्रभावित 15 ओवर के मैच में पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 9 विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की, जिसमें यश ढुल का शानदार शतक भी शामिल था। पहले बैटिंग करने के लिए बुलाए जाने पर, पुरानी दिल्ली 6 की टीम जल्दी ही ढेर हो गई क्योंकि सेंट्रल दिल्ली किंग्स के पेसर मनी ग्रेवाल ने टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। किंग्स ने नौवें ओवर में अपने विरोधियों का स्कोर 55/5 कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। जब पारी मुश्किल में थी, तो रोहन राठी और अश्विनी छिल्लर ने मिलकर टीम को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 85 रन की अहम पार्टनरशिप की, जिससे पुरानी दिल्ली 6 को मुश्किल स्थिति से उबरने में मदद मिली।

सेवा सेतु - हर नागरिक तक सरल, सहज और समयबद्ध सेवाएँ

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनकेंद्रित प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, त्वरित एवं सहज रूप से पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में शुरू की गई ''सेवा सेतु'' पहल शासन और आम नागरिक के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम बन रही है। कोरबा जिले के ग्राम ढंगुरडीह, तहसील भैंसमा निवासी शिव कुमार राठिया को अपने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे दोनों पुत्रों के शैक्षणिक कार्यों के लिए निवास एवं आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में बच्चों के शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। ऐसे में उन्होंने बिना किसी विलंब के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा सेतु केंद्र का रुख किया। सेवा सेतु केंद्र में कर्मचारियों ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना तथा आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया। मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद राठिया ने वहीं आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उनका प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत किया गया और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवास एवं आय दोनों प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए गए। राठिया ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सरल, सहज एवं पारदर्शी रही। उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा तथा समय पर दस्तावेज प्राप्त होने से उनके बच्चों के शैक्षणिक कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि यदि सेवा सेतु जैसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, तो उन्हें विभिन्न शासकीय कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम दोनों की अनावश्यक व्यय होता। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ की गई सेवा सेतु पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह व्यवस्था आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं तक त्वरित, सरल और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित कर रही है। राठिया ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित को केंद्र में रखकर संचालित इस पहल से आम नागरिकों को वास्तविक राहत मिल रही है।

महतारी वंदन योजना से पूर्णिमा के हाथों में आया आर्थिक संबल, बढ़ा आत्मविश्वास नियमित सहायता से परिवार की जरूरतें पूरी करना हुआ आसान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। गृहणी पूर्णिमा मानिकपुरी के लिए एक समय ऐसा भी था, जब घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। परिवार की सीमित आय में बच्चों की पढ़ाई, कॉपी-किताब, घरेलू सामान और अचानक होने वाले इलाज के खर्च की व्यवस्था करना कई बार मुश्किल हो जाता था। कबीरधाम जिले के ग्राम जीताटोला की रहने वाली पूर्णिमा ऐसे में उन्हें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। योजना के तहत हर महीने सीधे बैंक खाते में मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि ने उन्हें आर्थिक संबल ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी दी है। अब तक उन्हें 29 किस्तों के माध्यम से कुल 29 हजार रुपये प्राप्त हो चुके हैं। पूर्णिमा बताती हैं कि पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी-किताब खरीदना, घर का जरूरी सामान लाना या अचानक दवा की जरूरत पड़ने पर पैसों की चिंता सताने लगती थी। लेकिन अब हर महीने मिलने वाली राशि से ये सभी जरूरी काम समय पर हो जाते हैं। इससे परिवार का मासिक बजट भी संतुलित रहता है और आर्थिक दबाव काफी कम हो गया है। वे मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अब मुझे छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों की पढ़ाई हो, घर का जरूरी सामान हो या दवा का खर्चकृहर महीने मिलने वाली यह राशि मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई है। सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब मैं भी परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी भागीदारी निभा पा रही हूं। पूर्णिमा मानिकपुरी ने बताया कि इस योजना ने उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। अब उनके पास अपनी जरूरतों और परिवार की आवश्यकताओं के लिए स्वयं की राशि रहती है। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा है और वे बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को भी पूरा कर पा रही हैं। वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन गई है। यह सहायता राशि हर महीने परिवार के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनकर आती है और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020– व्यावसायिक विषयों के ब्लूप्रिंट निर्माण के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित 6 डोमेन पर तैयार होंगे कम्पीटेंसी आधारित प्रश्नपत्र

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप वोकेशनल विषयों के ब्लूप्रिंट निर्माण हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6 अगस्त 2026 तक चलने वाली यह कार्यशाला मण्डल की अध्यक्ष मती रेणु जी. पिल्ले के संरक्षण, सचिव मती पुष्पा साहू के निर्देश तथा एनसीईआरटी के परख (PARAKH) नई दिल्ली की विभागाध्यक्ष डॉ. इन्द्राणी भादुरी के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। 5 नए वोकेशनल ट्रेड शामिल किया गया है, जिसमें कक्षा 11वीं के लिए एपैरल एंड मेड-अप्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, प्लम्बिंग, पावर तथा कंस्ट्रक्शन ट्रेडों के नए ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर भविष्य में दक्षता (कम्पीटेंसी) आधारित प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों की समझ, कौशल और अधिगम परिणामों का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा।

गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन पर जोर: प्रशिक्षण के दौरान मण्डल के उपसचिव डॉ. बी. रघु ने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार करते समय सीखने के परिणामों, दक्षताओं, शैक्षणिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई के स्तर का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मण्डल की सचिव मती पुष्पा साहू ने बताया कि दक्षता- आधारित प्रश्नों के निर्माण से छात्रों में विषय की मौलिक समझ विकसित होगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रश्नपत्र निर्माण, सेटिंग और मॉडरेशन से जुड़े विषयों पर प्रतिभागियों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

विशेषज्ञ और मार्गदर्शक: यह कार्यशाला परख सेल के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार साहू के मार्गदर्शन में संचालित हो रही है। इसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉ. माधुरी बोरेकर, मती सीमा वर्मा, सहायक प्राध्यापक अखिलेश बावनगड़े, मती अलका जैन, मती मनीषी सिंह एवं मती शिवा सोमवंशी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (TRI) ने समावेशी ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ की साझेदारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छठे 'इंडिया रूरल कोलोक्वी' (भारत ग्रामीण संगोष्ठी) के छत्तीसगढ़ चैप्टर की शुरुआत इस ज़ोरदार अपील के साथ हुई कि छोटे किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों को ग्रामीण बदलाव की नींव के तौर पर पहचाना जाए। टीआरआई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच यह सहयोग पूरे राज्य में समावेशी और सामुदायिक नेतृत्व में होने वाले ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है। रायपुर में गोष्ठी का उ?द्घाटन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव और 'गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस' विभाग के सचिव, राहुल भगत ने कहा, 'छोटे किसान और स्वयं-सहायता समूहों की महिलाएँ ग्रामीण बदलाव की असली प्रेरक हैं। पहला कदम उठाने का उनका साहस असंख्य लोगों को बदलाव लाने वाला (चेंजमेकर) बनने के लिए प्रेरित करता है।' इस चर्चा में नया रायपुर के ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विकास कार्यों से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का काम किया गया। इससे पता चला कि कैसे मज़बूत ज़मीनी नेतृत्व, जवाबदेह संस्थान और सामुदायिक ज्ञान मिलकर ग्रामीण छत्तीसगढ़ के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 'ग्रीन इकोनॉमिक पाथवेज़ - छत्तीसगढ़' स्टडी रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें जलवायु-अनुकूल और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य भाषण देते हुए, पद्म पुरस्कार विजेता बुद्री थाती ने स्थानीय समुदायों और प्रकृति के बीच तालमेल को फिर से स्थापित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, 'जहाँ कभी बदलाव मुश्किल लगता था, वहाँ प्यार और सच्ची कोशिशों से बदलाव आया। हर इंसान प्यार चाहता है और उन्हें बस ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उन्हें सच में समझे।' मजबूत स्थानीय संस्थानों के महत्व पर बात करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि टिकाऊ ग्रामीण विकास ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, 'हर सरकारी योजना का असली क्रियान्वयन गांव के स्तर पर होता है।

अगर गाँव के संस्थान मजबूत नहीं होंगे, तो विकास की गति सीमित ही रहेगी।' वर्ष 2016 में स्थापित ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर स्थानीय नेतृत्व पर आधारित समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 2026 में अपने दूसरे दशक में प्रवेश करते हुए, यह लैंगिक समानता पर केंद्रित अपने दृष्टिकोण को और मजबूत कर रहा है तथा समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडलों का विस्तार कर ग्रामीण भारत में समान और सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, टीआरआई ने 'विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जमीनी नेतृत्व' विषय पर भारत ग्रामीण संगोष्ठी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। नीति-निर्माताओं, विचारकों और जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों ने इस बात पर अपने विचार साझा किए कि ग्रामीण बदलाव की अगली पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा। इसमें यह भी चर्चा की गई कि सार्वजनिक संस्थान समुदायों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसे तैयार कर सकते हैं। इस गोष्ठी का एक मुख्य आकर्षण 'ग्राम संवादः ग्रामीण भारत का भविष्य गढ़ते समुदाय' था। यह अपनी तरह की पहली चर्चा थी जिसमें नीतिगत चर्चाओं के केंद्र में समुदाय की आवाज़ को रखा गया।

13 कार्यों के लिए 3 करोड़ स्वीकृत उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका में 13 कार्यों के लिए 3 करोड़ 64 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने बैकुंठपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-19, जूनापारा में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 13 लाख 34 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-14 में जयस्तंभ चौक परिसर में निर्माण एवं संधारण कार्यों के लिए 15 लाख 46 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने दो पाथवे के निर्माण के लिए 50 लाख 45 हजार रुपए की मंजूरी दी है। इनमें मेन रोड राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के दोनों तरफ एसईसीएल ऑफिस से मुक्तिधाम तक पाथवे के लिए 13 लाख 66 हजार रुपए तथा मेन रोड राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के दोनों तरफ प्रमिला होंडा से नगर पालिका परिसर तक पाथवे के लिए 36 लाख 39 हजार रुपए की राशि शामिल है। नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड क्रमांक-16 में प्रेमाबाग कुमार वाटिका के पीछे गेज नदी में घाट निर्माण के लिए 10 लाख 29 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-17 में नया बस स्टैंड के पास इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए 18 लाख 70 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-14 में सिविल लाइन मानस भवन के पास पार्क निर्माण के लिए 20 लाख एक हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-15 में इंदिरा पार्क में मरम्मत एवं संधारण के लिए 18 लाख 37 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने तीन बी.टी. रोड की मरम्मत के लिए कुल 89 लाख 91 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इनमें वार्ड क्रमांक-16 में इंदिरा पार्क के सामने से जनपद तिराहा तक बी.टी रोड मरम्मत के लिए 48 लाख 54 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-9 में महलपारा तिराहा से शर्मा हॉस्पिटल लाइन होते हुए बिजली ऑफिस तक बी.टी. रोड मरम्मत के लिए 24 लाख 82 हजार रुपए एवं वार्ड क्रमांक-19 में बिजली ऑफिस से जूनापारा रोड तक बी.टी. रोड की मरम्मत के लिए 16 लाख 55 हजार रुपए की राशि शामिल है। विभाग ने बैकुंठपुर नगर पालिका में दो बी.टी. सड़कों के निर्माण के लिए भी 64 लाख 11 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें वार्ड क्रमांक-7 में अग्रवाल सिटी में बी.टी. रोड के लिए 49 लाख 64 हजार रुपए और महलपारा मेन रोड के पास बी.टी. सड़क के निर्माण के लिए 14 लाख 47 हजार रुपए की राशि शामिल है।

उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम के 129 शालाओं में बालिका शौचालय को मिली स्वीकृति

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कबीरधाम जिले के 129 शासकीय माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शालाओं में बालिकाओं को शौंचालय का अधिकार दिलाने के लिए 5 करोड़ 53 लाख 90 हजार रुपए की लागत से निर्माण को विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शौचालय के निर्माण के लिए विभिन्न स्कूलों की सूची जिला पंचायत को प्रस्तुत की गई थी। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि स्कूली बच्चों के सुविधाओं में विस्तार करते हुए स्वच्छ कबीरधाम की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया जा सके। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि इस नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के साथ स्कूलों में बच्चों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। इसी क्रम में यह स्वीकृति ग्रामीण बालिकाओं के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी।

ग्राम पंचायतें करेंगी निर्माण कार्य: इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि समुदाय के लिए बालिका शौचालय का निर्माण प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में कराया जा रहा है। निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को एजेंसी निर्धारित किया गया है। प्रत्येक स्कूलों में 4 लाख 30 हजार रुपए की लागत से कार्य स्वीकृत किया गया है। सभी कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश कार्य एजेंसी को दिए गए हैं तथा मैदानी कर्मचारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर करने कहां गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जनपद पंचायत बोड़ला क्षेत्र के 25 शालाओं हेतु 1 करोड़ 7 लाख 50 हजार रुपए, जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्र में 3 शालाओं के लिए 12 लाख 90 हजार रुपए, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र के 15 शालाओं हेतु 64 लाख 50 हजार रुपए एवं जनपद पंचायत पंडरिया क्षेत्र के 86 शालाओं हेतु 3 करोड़ 69 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। वीबी जीरामजी से ग्रामीणों को रोजगार और बालिकाओं को मिलेंगे सर्व सुविधा युक्त शौचालय शौचालय निर्माण से शालाओं में बालिकाओं के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा तथा निर्माण कार्य से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को प्रतिदिन 300 रूपए का मजदूरी भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। इस तरह 129 शौचालय के निर्माण कार्य से लगभग 75 से 80 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान ग्रामीणों को सीधे उनके खाते में प्राप्त हो जाएगा।

मोर गांव-मोर पानी अभियान से ग्रामीण आजीविका को मिली नई उड़ान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित मोर गांव-मोर पानी अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले में आजीविका आधारित जल संरचनाओं का निर्माण कर किसानों को कृषि एवं मत्स्य पालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

47 आजीविका डबरियों का निर्माण स्वीकृत: जांजगीर-चांपा जिले में अभियान के तहत कुल 47 आजीविका डबरियों का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 35 डबरियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्षा जल से भर चुकी इन डबरियों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है, जिससे खेती का रकबा बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। 14 डबरियों में मत्स्य पालन एवं कृषि आधारित गतिविधियां संचालित आजीविका डबरियां अब केवल जल संरक्षण का माध्यम नहीं रहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का सशक्त स्रोत भी बन रही हैं। वर्तमान में 14 डबरियों में मत्स्य पालन एवं कृषि आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। डबरियों की मेड़ों पर दलहन, तिलहन तथा अन्य फसलों की खेती से किसानों को अतिरिक्त उत्पादन और बेहतर आमदनी प्राप्त हो रही है। जिले में 4 डबरियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्षा जल संरक्षण, भू-जल स्तर में सुधार तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिली है। इससे किसान अब वर्षभर कृषि एवं मत्स्य पालन जैसी आजीविका गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं।

मोर गांव-मोर पानी अभियान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणः मोर गांव-मोर पानी अभियान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रहा है। यह अभियान जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान कर रहा है।

पैडी ट्रांसप्लांटर से किसान डिकेश्वर साहू ने घटाई लागत, बढ़ाई उत्पादकता

25 एकड़ में धान की खेती, प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपए की बचत के साथ समय और श्रम की हुई बचत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी और किफायती बना रहे हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती में लागत कम होने के साथ उत्पादकता भी बढ़ रही है। इसी दिशा में बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम खल्लारी निवासी प्रगतिशील किसान डिकेश्वर कुमार साहू ने पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई मशीन) के उपयोग से खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

25 एकड़ में आधुनिक तकनीक से धान की रोपाई: किसान डिकेश्वर साहू लगभग 25 एकड़ भूमि में धान की खेती करते हैं। पहले धान रोपाई के समय उन्हें मजदूरों की कमी और बढ़ती मजदूरी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई कराने पर प्रति एकड़ लगभग 8 हजार रुपये का खर्च आता था। कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्होंने पहले हाथ से चलने वाला पैडी ट्रांसप्लांटर अपनाया। इससे मिले सकारात्मक परिणामों के बाद उन्होंने इस वर्ष छह लाइन वाला आधुनिक पैडी ट्रांसप्लांटर खरीदा, जिससे खेती और अधिक आसान एवं लाभकारी हो गई।

प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपये की बचतः डिकेश्वर साहू ने बताया कि आधुनिक मशीन के उपयोग से धान रोपाई की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहां प्रति एकड़ लगभग 8 हजार रुपए खर्च होते थे, वहीं अब मशीन के माध्यम से यह खर्च घटकर लगभग 1 हजार रुपए प्रति एकड़ रह गया है। इस प्रकार उन्हें प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपए की बचत हो रही है। साथ ही 25 एकड़ में रोपाई का कार्य कम समय में पूरा हो जाने से श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है।

● बेहतर रोपाई से बढ़ी फसल की गुणवत्ता ●

पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करने पर पौधों के बीच समान दूरी बनी रहती है, जिससे प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप फसल का बेहतर विकास होता है और उत्पादन बढ़ने की संभावना भी अधिक रहती है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से खेती वैज्ञानिक और अधिक लाभकारी बन रही है।

● अन्य किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील ●

किसान डिकेश्वर साहू ने जिले के अन्य किसानों से भी आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों को धान का बेहतर मूल्य मिल रहा है। ऐसे में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और यंत्रीकरण को अपनाकर कम लागत, कम समय और अधिक उत्पादन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि आधुनिक खेती ही भविष्य की समृद्ध खेती है और यही किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी है।